



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 12, 2017/वैशाख 22, 1939

No. 129]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 12, 2017/VAISAKHA 22, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2017

अंतिम जांच परिणाम

विषय: चीन जनवादी गणराज्य मूल की अथवा वहां से निर्यातित “पेनटेरीथ्रिटोल” के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने संबंधी निर्णायक समीक्षा में अंतिम जांच परिणाम।

सं. 15/01/2016-डीजीएडी.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटन-रोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियम भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने चीन जनवादी गणराज्य और स्वीडन मूल के अथवा वहां से (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) निर्यातित “पेनटेरीथ्रिटोल” (जिन्हें आगे संबद्ध वस्तुएं भी कहा गया है) के आयातों पर दिनांक 4 फरवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या 14/16/2004-डीजीएडी द्वारा पाटन-रोधी जांच शुरू की थी। इस जांच के प्रारंभिक जांच परिणाम को 5 अगस्त, 2005 को अधिसूचित किया गया था। प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य और स्वीडन मूल के अथवा वहां से (निर्यातित “पेनटेरीथ्रिटोल” के आयातों पर निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क लगाने संबंधी अंतिम जांच परिणाम को 2 फरवरी, 2006 को अधिसूचित किया था। उक्त अंतिम निर्णय के आधार पर राजस्व विभाग ने दिनांक 20.04.2006 की अधिसूचना संख्या 037/2006-सीमा शुल्क द्वारा संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं पर ऐसा सुनिश्चित शुल्क लगाया था।

2. प्राधिकारी ने दिनांक 26 मार्च, 2010 की अधिसूचना संख्या 15/3/2010-डीजीएडी द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की थी। प्राधिकारी ने दिनांक 25 मार्च, 2010 की अधिसूचना संख्या 15/3/2010-डीजीएडी द्वारा चीन जनवादी

गणराज्य से आयातों पर निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क और पाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की थी और वित्त मंत्रालय की दिनांक 14 जून, 2011 की अधिसूचना संख्या 47-2011/सीमा-शुल्क द्वारा चीन जनवादी गणराज्य मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क को आगे बढ़ा दिया गया था। तथापि, निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी ने स्वीडन से आयातों पर लगे पाटन-रोधी शुल्क को रद्द कर दिया था।

3. और उपरोक्त स्थिति होने के बावजूद प्राधिकारी को ऐसे उपाय की समाप्ति की तारीख से पहले उचित समय-अवधि के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से विधिवत् पर्याप्त साक्ष्यों के साथ किए गए अनुरोध पर इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है कि क्या शुल्क को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के निरंतर रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

4. और यतः मेसर्स कनोडिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे आगे "याचिकादाता" अथवा "आवेदक" कहा गया है) ने अधिनियम और पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार वर्तमान मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करके चीन जनवादी गणराज्य मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पेनोटेरीश्रिटोल" (जिन्हें आगे संबद्ध वस्तुएं भी कहा गया है) के सभी आयातों पर निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्कों का विस्तार करने को अनुरोध किया है।

5. और यतः प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के यथोचित सिद्ध करने के लिए प्रदत्त पर्याप्त प्रमाणों के आधार पर दिनांक 7 जून, 2016 की अधिसूचना संख्या 15/01/2016-डीजीएडी द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने की वैधता को केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 13 जून, 2016 की अधिसूचना संख्या 26/2016-सीमा-शुल्क (एडीडी) द्वारा 13 जून, 2017 तक बढ़ा दिया गया था।

6. वर्तमान समीक्षा के कार्यक्षेत्र में चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित उपर्युक्त वस्तुओं के आयातों से संबंधित मूल जांच के सभी पहलू शामिल हैं।

ख. प्रक्रिया

7. प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त जांच शुरू करने के लिए सार्वजनिक अधिसूचना जारी करने के बाद इस जांच के संबंध में निम्नोक्त वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है:

- i. प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमावली के नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्रवाई शुरू करने से पहले पाटनरोधी आवेदन पत्र प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास/प्रतिनिधियों को सूचित कर दिया था।
- ii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास को, आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, और भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, अन्य भारतीय उत्पादकों और घरेलू उद्योग को जांच शुरू संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी भी और उनसे अनुरोध किया था कि वे जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत करा दें।
- iii. प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को आवेदन पत्र के अगोपनीय वृत्तांत की एक प्रति प्रदान की थी।
- iv. भारत स्थित संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे चीन से उत्पादकों/निर्यातकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने उत्तर प्रस्तुत करने की सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को प्रेषित किए गए पत्र की एक प्रति और प्रश्नावली, चीन जनवादी गणराज्य से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और उनके पतों के साथ उन्हें प्रेषित की गई थी।

V. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार प्राधिकारी ने संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों से संगत सूचना मंगाने के लिए उन्हें निर्यातक की प्रश्नावलियां और बाजार अर्थव्यवस्था की प्रश्नावलियां प्रेषित की थीं:

- (क) मैसर्स हुबेई यिहुआ ग्रुप लिमिटेड लिएबिलिटी कंपनी
- (ख) मैसर्स गुईझोऊ क्रिस्टल केमिकल कं. लि.
- (ग) मैसर्स चाइना नेशनल केमिकल्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन

- (घ) मैसर्स सिनोचेम जियांग्सु इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन
- (ङ) मैसर्स शांक्षी सनवेई ग्रुप कंपनी लि.
- VI. उपर्युक्त अधिसूचना के प्रत्युत्तर में किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्रश्नावली के प्रत्युत्तर नहीं दिए हैं अथवा प्रस्तुत नहीं किए हैं।
- VII. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं के लिए आयातक की प्रश्नावलियां भेजी थीं:
- (क) एडिसन पेंट्स एंड केमिकल लि.
- (ख) बर्गर पेंट्स इंडिया लिमिटेड
- (ग) सेंचुरी एंका लिमिटेड
- (घ) सीबा स्पेशियलिटी केमिकल्स (इंडिया) लि.
- (ङ) कोट्स ऑफ इंडिया लि.
- (च) डेक्रो पेंट्स
- (छ) डुजोडवाला पेपर केमिकल्स लि.
- (ज) गार्गी इंडस्ट्रीज प्रोप.
- (झ) गुडलेस नेरोलेक पेंट्स लि.
- (ञ) हार्डकास्टले एंड वॉड मैन्यु. कं. लि.
- (ट) हीरो डार्ई केम. इंडस्ट्रीज
- (ठ) हिंदुस्तान इंक्स एंड रेसिन्स लि.
- (ड) आईवीपी लि.
- (ढ) जेंसन एंड निकोल्सन (आई) लि.
- (ण) मित्सुइंड्स लिमिटेड
- (त) पारस डार्ईज एंड केमिकल्स
- (थ) रेसिन एंड पिगमेंट्स
- (द) पर्सटॉर्प केमिकल्स इंडिया प्रा. लि.
- (ध) ए.वी.एम. सेल्स प्रा. लि.
- (न) एल्कन इंटरप्राइजेज
- (न) केमिकलर एजेंसी
- (प) ईस्टकॉर्प इंटरनेशनल
- (फ) गडवाढे पॉलीस्टर लि.
- (ब) एच. आर. ट्रेडिंग कं. प्रा. लि.
- (भ) लियो केमोप्लास्ट प्रा. लि.
- (म) समीर डार्ई केम.
- (य) सनमान ट्रेड इम्पैक्स प्रा. लि.
- (र) सराफ केमिकल्स लि.

(ल) विबग्योर पैंट्स प्रा. लि.

(व) शालीमार पैंट्स लि.

- VIII. किसी भी आयातक ने आयातकों की प्रश्नावली के निवेदन अथवा प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं।
- IX. प्राधिकारी ने विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणों के अगोपनीय वृत्तांत को सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध करा दिया है, जो कि हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण के लिए खुली पड़ी हुई है।
- X. वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वे जांच अवधि और पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए किए गए कारोबार-वार आयात के विस्तृत आंकड़े उपलब्ध कराएं जो कि प्राधिकारी को प्राप्त हो गए हैं। प्राधिकारी ने आयात की मात्रा का परिकलन करने के लिए तथा कारोबार की विधिवत जांच करने के बाद अपेक्षित विश्लेषण करने के लिए डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त हुए आंकड़ों पर विश्वास किया है। कारोबार-वार आयात के आंकड़ों को सार्वजनिक फाइल पर उपलब्ध कराया गया है।
- XI. सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की अनुकूलतम लागत और निर्माण की लागत के आधार पर उसकी क्षतिरहित कीमत का आकलन किया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यदि पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है, तो क्या वह घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- XII. प्राधिकारी ने नियम 6(6) के प्रावधान के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों को अपने मौखिक विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए 19 सितंबर, 2016 को मौखिक सुनवाई की थी, जिसमें घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों ने ही भाग लिया था। मौखिक सुनवाई के समय जिन हितबद्ध पक्षकारों ने अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त किए थे, ऐसे घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों को सलाह दी गई थी कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें।
- XIII. निर्दिष्ट प्राधिकारी की पदावधि में परिवर्तन हो जाने की स्थिति में तथा एटीएमए के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, नए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 6 फरवरी, 2016 को अन्य मौखिक सुनवाई की थी जिसमें घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। घरेलू उद्योग के जिन प्रतिनिधियों ने अपने विचारों को मौखिक रूप से व्यक्त किया था, उनसे अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें।
- XIV. घरेलू उद्योग के आंकड़ों की मौके पर जांच करने के साथ-साथ जितना आवश्यक समझा गया था, सहयोगी निर्यातकों के आंकड़ों की भी उतनी जांच की गई है। केवल ऐसी सत्यापित सूचना को, जहां कहीं भी आवश्यक था, उसमें आवश्यक संशोधन सहित इस अंतिम परिणाम में उन पर विश्वास किया गया है।
- V. मौजूदा समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि, अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 (12 महीने) है। तथापि, क्षति का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ जांच में अप्रैल, 2012-मार्च, 2013, अप्रैल, 2013-मार्च, 2014, अप्रैल, 2014-मार्च, 2015 और जांच की अवधि (पीओआई) शामिल हैं।
- XVI. इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को प्राधिकारी द्वारा जहां कहीं भी प्रासंगिक पाया गया है, वहां उनका निदान इस अंतिम जांच परिणाम में किया गया है।
- XVII. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनायता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय वृत्तांत भी प्रस्तुत करें।
- XVIII. मौजूदा जांच की कार्रवाई के दौरान जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने आवश्यक सूचना देने से मना कर दिया है अथवा ऐसी सूचना अन्यथा प्रदान नहीं की है अथवा जांच में अत्यधिक अड़चन डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपना निर्णय रिकार्ड किया है।

- XIX. संबंधित नियमावली के नियम 16 के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकार को 14 मार्च 2017 को अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन किया। 20 मार्च, 2017 तक टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। प्रकटन विवरण के संबंध में प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई टिप्पणियों पर इन अंतिम जांच परिणामों में विचार किया गया है।
- XX. इस अंतिम निर्णय में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा *** सूचना को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया गया है।
- XXI. प्राधिकारी द्वारा इस जांच के लिए अपनाई गई औसत विनिमय दर, 1 अमेरिकी डॉलर = 65.91 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 घरेलू उद्योग के विचार

8. घरेलू उद्योग के विचार निम्नानुसार हैं:

- वर्तमान समीक्षा जांच एक निर्णायक जांच होती है। मूल जांच में तथा वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में निहित उत्पाद पेंटायरीथ्रिटल है। वर्तमान निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। पेंटायरीथ्रिटल सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत एक आर्गेनिक केमिकल है। तथापि, जांच के कार्यक्षेत्र में डि-पेंटायरीथ्रिटल शामिल नहीं होता है। दो ग्रेडों तकनीकी और नाइट्रेशन में इसका उत्पादन और विपणन होता है। तथापि, इन दोनों ग्रेडों के बीच में वस्तुतः कोई अंतर नहीं पाया गया है तथा दोनों ग्रेडों का समान प्रक्रिया से ही उत्पादन होता है। उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान पेंटा के समस्त उत्पादन का 2 प्रतिशत से कम उत्पादन नाइट्रेशन ग्रेड के उत्पादन से होता है, जबकि 97 प्रतिशत से अधिक उत्पादन तकनीकी ग्रेड के रूप में होता है।
- पेंटायरीथ्रिटल का आल्किड रेसिन, रेसिन ईस्टर्स, प्लास्टिकाजर्स, प्रिंटिंग इंक, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक के लिए स्टेविलाजर्स, संशोधित ड्राइंग ऑयल, डेटोनेटर्स, विस्फोटकों, फार्मास्युटिकल्स, कोर ऑयल और सिंथेटिक स्नेहकों का विनिर्माण करने में उपयोग किया जाता है। संबद्ध वस्तुएं उप शीर्षक संख्या 2905.42 के तहत अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत आती हैं। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल निर्देशात्मक है और यह वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर किसी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।
- घरेलू और आयातित उत्पाद में नियोजित प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता के बीच में कोई अंतर नहीं है। वर्तमान जांच एक समीक्षा जांच है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के मुद्दे की जांच की है जिस पर विश्वास किया है।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

9. किसी भी आयातक, निर्यातक और किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तुओं के बारे में कोई टिप्पणी अथवा निवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

ग.3 प्राधिकारी के द्वारा जांच

10. विचाराधीन उत्पाद पेंटायरीथ्रिटल एक आर्गेनिक मिश्रण है जो आल्किड रेसिन, रेसिन ईस्टर्स प्लास्टिकाजर्स, प्रिंटिंग इंक, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक के लिए स्टेविलाजर्स, संशोधित ड्राइंग ऑयल, डेटोनेटर्स, विस्फोटकों, फार्मास्युटिकल्स, कोर ऑयल और सिंथेटिक स्नेहकों का विनिर्माण करने में अनुप्रयोग पाया जाता है। पेंटायरीथ्रिटल तकनीकी ग्रेड अथवा नाइट्रेशन ग्रेड का हो सकता है और दोनों ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र और वर्तमान जांच के भीतर शामिल हैं। पेंटायरीथ्रिटल सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधिनियम के अध्याय 29 के तहत सीमा शुल्क उप शीर्षक संख्या 2905.42 के अंतर्गत वर्गीकृत है।

11. वर्तमान जांच, एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के बारे में तथा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं आयातों पर प्रभावी पाटनरोधी शुल्कों के बारे में, जिनकी प्राधिकारी ने पहले सिफारिश की थी, प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का कार्यक्षेत्र वही रहता है, जो पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार मूल और बाद में समीक्षा जांच में है।

12. रिकार्ड की गई सूचना के बारे में विचार करने के बाद में प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और भारतीय उद्योग के द्वारा उत्पादित उत्पाद के बीच में कोई ज्ञात अंतर नहीं होता है। घरेलू उद्योग के द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं वास्तविक और रासायनिक विशेषताओं, कार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विशिष्टियों, वितरण और

विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ संबंधी वर्गीकरण के आधार पर विचाराधीन उत्पाद से तुलनीय होती है। दोनों विशेषताएं तकनीकी एवं वाणिज्यिक तौर पर प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता परस्पर परिवर्तनीय दोनों विशेषताओं का उपयोग कर रहे हैं।

13. अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक घरेलू उद्योग के द्वारा उत्पादित संबद्ध उत्पाद पाटनरोधी नियमावली के अनुसार विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र और आधार

घ.1 घरेलू उद्योग के विचार

14. घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग के द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं:

- i. मै. कनौडिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लि. के द्वारा विचाराधीन उत्पाद के एक घरेलू उत्पादक के रूप में याचिका दायर की गई थी। देश में पेंटायरीथ्रिटल के दो उत्पादक हैं। याचिकाकर्ता के अलावा, संबद्ध वस्तुओं का एशियन पेंट्स (इंडिया) लि. द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। यद्यपि एशियन पेंट्स मुख्यतः आबद्ध उपभोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन करती है, परंतु इसने प्रासंगिक अवधि में भारतीय बाजार में कुछ बिक्रियां भी की हैं। इसके अलावा, आबद्ध खपत की सीमा तक एशियन पेंट्स के उत्पादन में पात्र उत्पादन शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि यह उत्पादन विदेशी उत्पादकों के द्वारा आपूर्ति की गई पाटित सामग्री अथवा भारतीय उत्पादकों के द्वारा की गई बिक्रियों का मुकाबला नहीं करता है।
- ii. पूर्व जांचों में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक नामतः परस्टोर्प केमिकल्स प्रा. लि. का (जिसे इसके बाद में "परस्टोर्प इंडिया" कहा जाएगा) वर्ष 2009-10 के बाद से कोई घरेलू उत्पादन नहीं है और इसे विचाराधीन उत्पाद का काफी समय से एक भारतीय उत्पादक के रूप में नहीं माना जाता है। अन्य स्रोतों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पूर्व में की गई पाटनरोधी जांच में यह सुनिश्चित किया गया है कि परस्टोर्प इंडिया संबद्ध वस्तुओं का एक आयातक है और यह विदेशों में अपनी संबद्ध कंपनियों से लदान (शिपमेंट) प्राप्त करती है।
- iii. अतः मैसर्स कनौडिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लि. भारत में संबद्ध वस्तुओं का केवल पात्र घरेलू उत्पादक है और यह नियमावली 1995 के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग बनती है।
- iv. याचिकाकर्ता का उत्पादन, भारतीय उत्पादन में (एशियन पेंट्स के द्वारा आबद्ध खपत को शामिल करने और बाहर करने दोनों के बाद) एक बड़ा अनुपात बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता को नियमावली के अर्थ के भीतर "घरेलू उद्योग" के रूप में मानना चाहिए।
- v. याचिकाकर्ताओं ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और यह चीन में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से अथवा नियमावली 2(ख) के अर्थ में भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक अथवा प्रयोक्ता से संबंधित नहीं है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

15. किसी भी उत्पादक/निर्यातक/आयातक/अन्य हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई निवेदन नहीं किया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

16. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

17. आवेदन पत्र मैसर्स कनौडिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लि. द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अन्य ज्ञात उत्पादक एशियन पेंट्स (इंडिया) लि. आबद्ध खपत के लिए संबद्ध वस्तुओं का भी उत्पादन करती है।

18. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी को इसकी जांच करने की आवश्यकता है कि क्या (क) आवेदन पत्र का समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का उत्पादन, घरेलू उद्योग द्वारा किए जाने वाले समान वस्तु के कुल उत्पादन का 25

प्रतिशत से भी अधिक अंश बनता है और (ख) आवेदन-पत्र को ऐसे घरेलू उत्पादकों का समर्थन प्राप्त है, जिनका सामूहिक आउटपुट, समान वस्तु के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से भी अधिक बनता है जो कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित किए जाने वाला अंश है, जो कि जैसी भी स्थिति है, उसका समर्थन अथवा विरोध व्यक्त करता है। एशियन पेंट्स के द्वारा आवद्ध खपत के लिए उत्पादन को छोड़कर कुछ घरेलू उत्पादन में आवेदक का उत्पादन 69 प्रतिशत बनता है और एशियन पेंट्स के द्वारा आवद्ध खपत के लिए उत्पादन सहित कुल भारतीय उत्पादन में आवेदक का उत्पादन 52 प्रतिशत बनता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से अथवा नियमावली 2(ख) के अर्थ के भीतर भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक अथवा प्रयोक्ता से संबंधित नहीं है।

आवद्ध खपत को छोड़कर उत्पादन

	विवरण	यूओएम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	याचिकाकर्ता	मी. टन	6,648	6,831	6,814	7,284
क	कनौडिया केमिकल्स	मी. टन	6,648	6,831	6,814	7,284
2	अन्य भारतीय उत्पादक	मी. टन	2,614	2,620	3,257	3,261
3	कुल भारतीय उत्पादन	मी. टन	9,262	9,451	10,072	10,546
	शेयर	यूओएम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	याचिकाकर्ता	%	71.78	72.28	67.66	69.08
2	कनौडिया केमिकल्स	%	71.78	72.28	67.66	69.08
3	अन्य भारतीय उत्पादक	%	28.22	27.72	32.34	30.92
4	कुल भारतीय उत्पादन	%	100.00	100.00	100.00	100.00

पीओआई: अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016

आवद्ध सहित भारतीय उत्पादन का विवरण

	विवरण	यूओएम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	याचिकाकर्ता	मी. टन	6,648	6,831	6,814	7,284
2	अन्य भारतीय उत्पादक	मी. टन	2,592	2,592	3,293	3,293
3	आवद्ध (याचिकाकर्ता + अन्य)	मी. टन	2,853	2,866	3,493	3,501
4	कुल भारतीय उत्पादन	मी. टन	12093	12,347	13,666	14,152
	शेयर	यूओएम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	याचिकाकर्ता	%	54.97	55.59	50.11	51.74
2	अन्य भारतीय उत्पादक	%	21.44	21.09	24.21	23.39
3	आवद्ध	%	23.59	23.32	25.68	24.87
4	कुल भारतीय उत्पादन	%	100	100	100	100

पीओआई: अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016

19. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और उचित जांच करने के बाद प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक आधार (स्थिति) संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के तहत घरेलू उद्योग बनता है।

ड. बाजार आर्थिक सुधार (एमईटी), सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

20. नियमावली के अंतर्गत "सामान्य मूल्य" का अर्थ है कि -

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क(1)(ग) के अनुसार, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप-धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित निर्यातक देश या भू-भाग में खपत के लिए नियत हो, अथवा

जब निर्यातक देश या भू-भाग के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या भू-भाग की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) *समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या भू-भाग से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा*

(ख) *उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;*

वशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम के देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु का निर्यात के देश से होकर केवल यानान्तरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम के देश में उसकी कीमत के संबंध में किया जाएगा।

ड.1 घरेलू उद्योग के विचार

21. घरेलू उद्योग, अन्य के साथ-साथ निम्नानुसार प्रस्तुत करता है:

क. प्राप्त आचार संहिता का एक उपबंध दिनांक 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हुआ है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को नीचे दिए गए कारणों से गैर-बाजार आर्थिक स्थितियों में प्रचालन कर रहे उत्पादकों के रूप में चीनी उत्पादकों पर विचार करते हुए वर्तमान जांच की कार्यवाही को आगे बढ़ाना चाहिए।

ख. वर्तमान मामले में प्राधिकारी द्वारा विचारित जांच की अवधि अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 (12 महीने) है। क्षति जांच अवधि को 2012-13, 2013-14, 2014-15 और पीओआई की अवधि के रूप में विचारित किया गया है।

ग. पीओआई के निर्धारण का प्रयोजन ऐसी अवधि पर विचार करना है जब पाटन के कारण क्षति की विद्यमानता का दावा किया जाता है और प्रमाणित किया जाता है। घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति के विवादास्पद पक्ष के लिए निर्धारण की तारीख संगत नहीं है। चूंकि, घरेलू उद्योग को पाटन के कारण हुई क्षति का परिमाण जांच अवधि के आधार पर स्थापित किया जाता है, जांच अवधि के दौरान अभिभावी स्थितियों को इस प्रयोजनार्थ संगत, उचित और आवश्यक समझा जाना चाहिए।

घ. चीनी उत्पादकों को इस कारण से गैर-बाजार आर्थिक कंपनियां माने जाने की जरूरत है कि चीन में लागत और कीमतें बाजार ताकतों को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करतीं। अनुबंध-1 का पैरा 8 उन मापदंडों को विनिर्दिष्ट करता है जिन पर बाजार की आर्थिक प्रास्थिति प्रदान करते समय विचार किया जाना चाहिए।

पैरा यह भी अंतर्निहित करता है कि जब तक इन स्थितियों को पूरा/संतुष्ट नहीं किया जाता, चीनी लागतों और कीमतों को अपनाया नहीं जा सकता।

- ड. बाजार आर्थिक प्रास्थिति का विचार जांच अवधि के दौरान अभिभावी मापदंडों पर आधारित है। चूंकि, चीनी लागतों और कीमतों की अस्वीकृति का कारण अनुबंध-1 के पैरा 8 में सूचीबद्ध कारकों के कारण चीन में लागतों और कीमतों में विरूपण है, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि जांच अवधि ही चीनी उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था कंपनियों के रूप में विचार किए जाने के निर्णय के लिए प्रासंगिक है।
- च. चूंकि, चीनी कंपनियों ने दिसंबर, 2016 तक अनुबंध-1 के पैरा 8 में उल्लिखित कारणों से बाजार अर्थव्यवस्था प्रास्थिति से इंकार किया है, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि चीनी उत्पादकों को उस समय तक गैर-बाजार व्यवस्था कंपनियों के रूप में माना जाना अनिवार्य है जिस समय तक जांच अवधि में संधि प्रोटोकॉल में निर्दिष्ट अवधि को शामिल किया जाता है।
- छ. नियम 2(ख) के संदर्भ में, यह एक स्थापित विधिक स्थिति है कि किसी घरेलू उत्पादक द्वारा किए गए आयात अथवा किसी निर्यातक या आयातक के साथ उसके संबंधों की जांच, जांच की अवधि के संदर्भ में की जाती है। यदि सिर्फ पीओआई स्थायी प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक है तो सिर्फ पीओआई को सामान्य मूल्य निर्धारणों के लिए भी प्रासंगिक होना चाहिए।
- ज. चीनी उत्पादकों को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वातावरण के अंतर्गत प्रचालन कर रही कंपनियों के रूप में माना जाना अपेक्षित है और प्राधिकारी अनुबंध-1 के पैरा 7 के आधार पर सामान्य मूल्य को निर्धारित करने के लिए आगे कार्रवाई कर सकते हैं।
- झ. सामान्य मूल्य को किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में प्रभावी कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर इस कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता कि संगत जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। याचिकाकर्ता ने सामान्य मूल्य के विचार का दावा भारत में भली-भांति समायोजित उत्पादन की लागत के आधार पर किया है।
- ञ. चीन से पाटन मार्जिन न केवल उल्लेखनीय है बल्कि पर्याप्त भी है, अतः भारत में विचाराधीन उत्पाद के उल्लेखनीय पाटन की मौजूदगी को स्थापित करता है। चीन से आयात की मात्रा लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद, पूरी वर्तमान क्षति अवधि के दौरान उल्लेखनीय बनी रही है।
- ट. चीनी उत्पादकों के पास उपलब्ध उत्पादन क्षमताओं और उनकी उच्च निर्यात अनुकूलन को देखते हुए पाटन जारी रहेगा और पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में यह और अधिक गहन हो जाएगा।

ड.2 हितबद्ध पक्षकारों के विचार

22. किसी भी आयातक, प्रयोक्ता, निर्यातक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने पाटन मार्जिन के संबंध में कोई टिप्पणी या आवेदन दायर नहीं किए हैं।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

23. चीन की प्राप्ति आचार संहिता के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था की गई है:

"जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार 1994 पर सामान्य करार के अनुच्छेद VI के क्रियान्वयन पर करार ("पाटनरोधी करार") और एससीएम करार निम्नलिखित के संगत चीनी मूल के एक डब्ल्यूटीओ सदस्य के रूप में आयातों को शामिल करने वाली कार्रवाई पर लागू होगा:

(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता को निर्धारित करने में, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीनी कीमतों या लागतों अथवा ऐसे विधितंत्र का प्रयोग करेगा जो निम्नलिखित नियमों पर आधारित चीन में घरेलू कीमतों या लागतों की सख्त तुलना पर आधारित है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि उद्योग में प्रभावी बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियां उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन कर रही हैं तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य कीमत तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीनी कीमतों या लागतों का प्रयोग करेगा।

(iii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य ऐसे तंत्रविधि का प्रयोग कर सकते हैं जो चीन में घरेलू कीमतों या लागतों की सख्त तुलना पर आधारित न हो यदि जांचाधीन उत्पादक यह स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाते कि उद्योग में अभिभावी बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियां इस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन कर रहा है।

(ख) एससीएम बाजार करार के भाग-II, III और V के अंतर्गत कार्रवाईयों में, जब अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में वर्णित आर्थिक सहायताओं का वर्णन किया जाता है तो एससीएम करार के संगत उपबंध लागू होंगे, हालांकि, यदि उस अनुप्रयोजन में विशेष कठिनाईयां सामने आती हैं तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य तब सब्सिडी लाभ की पहचान और मापन के लिए कार्य प्रणालियों का प्रयोग कर सकते हैं जो इस संभाव्यता को ध्यान में रखेगी कि चीन में अभिभावी निबंधन और शर्तें हमेशा एक उचित मार्क के रूप में उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी कार्य प्रणालियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य को चीन के बाहर अभिभावी निबंधन और शर्तों का प्रयोगन करने के बारे में विचार करने से पहले ऐसी अभिभावी निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य पाटनरोधी पद्धतियों पर समिति के उप पैराग्राफ (क) के अनुसरण में प्रयुक्त की गई कार्य प्रणालियों को अधिसूचित करेंगे और आर्थिक सहायता और समकक्ष उपायों पर समिति के उप पैराग्राफ (ख) के अनुसरण में प्रयुक्त कार्य प्रणालियों को अधिसूचित करेंगे।

आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य संबंधी राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत एक बार चीन द्वारा यह स्थापित किए जाने पर कि यह बाजार अर्थव्यवस्था है, उप पैराग्राफ (घ) के उपबंधों को समाप्त कर दिया जाएगा बशर्ते कि आयातक सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्त की तारीख के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था मानदंड को शामिल किया गया है। किसी भी स्थिति में, उप पैराग्राफ (क) (ii) के उपबंध प्राप्ति की तारीख के 15 वर्षों के बाद समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त, चीन द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए कि आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में किसी विशेष आयोग या क्षेत्र में लागू बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियों के कारण उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था उपबंध उस उद्योग या क्षेत्र पर आगे से लागू नहीं होंगे।

24. अनुच्छेद 15 का तात्पर्य है कि उप पैराग्राफों में से एक उपबंध चीन के परिग्रहण की तारीख से 15 वर्ष के बाद समाप्त हो जाएगा। इस पैराग्राफ का उपबंध 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया। चूंकि, घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाले पाटन के तथ्य जांचाधीन अवधि के आधार पर स्थापित किए गए हैं, सिर्फ जांचावधि के दौरान प्रभावी स्थितियां वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ संगत, उचित और अनिवार्य हैं। वर्तमान समीक्षा के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2015-मार्च, 2016 है। चूंकि, जांच की अवधि के दौरान अनुच्छेद 15 का उप पैराग्राफ अस्तित्व में था, प्राधिकारी एक ऐसी कार्यप्रणाली का प्रयोग कर सकते हैं जो चीन में घरेलू कीमतों या लागतों की सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह नहीं दर्शा सकते कि उद्योग में अभिभावी बाजार व्यवस्था स्थितियां उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद उत्पादित कर रही है।

25. प्राधिकारी ने टिप्पणी की है कि पिछले तीन वर्षों में, चीन जन गण को भारत और अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा पाटनरोधी जांचों में एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है। चीन जन गण को नियमावली के शर्तों में निर्यातक देश अथवा वैयक्तिक निर्यातकों द्वारा पूर्वानुमान के खंडन के अध्यधीन एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश माना गया है।

बाजार अर्थव्यवस्था दावों की जांच

26. यथा संशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 8 के अनुसार, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के पूर्वानुमान का खंडन नहीं किया जा सकता है यदि चीन जन गण के निर्यातक पैराग्राफ 8 के उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मानदंड के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराता है और उसके विपरीत प्रमाण प्रस्तुत करता है। चीन जन गण के जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के सहयोगी निर्यातक/उत्पादकों द्वारा अनिवार्य सूचना/पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराना अपेक्षित है जैसा कि बाजार अर्थव्यवस्था सुधार के प्रत्युत्तर में पैराग्राफ के उप पैराग्राफ (3) में उल्लेख किया गया है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मानदंड पर विचार करने में सक्षम हो सकें कि क्या:

क. क्या कच्ची सामग्री, प्रौद्योगिकी की लागत और श्रमिक, आउटपुट, बिक्री और निवेश सहित कीमतों, लागतों और इनपुट के संबंध में चीन जन गण से संबंधित फर्मों का निर्णय आपूर्ति को प्रतिबिंबित करने वाले बाजार

संकेतकों की प्रतिक्रिया में और इस संबंध में उल्लेखनीय राज्य के हस्तक्षेप के बिना किए जाते हैं और क्या प्रमुख इनपुट की लागत बाजार मूल्यों को उल्लेखनीय रूप से प्रतिबिंबित करती है।

- ख. ऐसी फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति औपचारिक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से प्राप्त की गई उल्लेखनीय विरूपताएं, विशेष रूप से परिसंपत्तियों के हास, अन्य बट्टे खाते, वस्तु विनिमय व्यापार और ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए अदायगी के अध्यक्षीन है।
- ग. ऐसी फर्में दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अध्यक्षीन है जो फर्मों के प्रचालन के लिए कानूनी सुनिश्चितता और स्थायित्व की गारंटी देती है।
- घ. विनिमय दर परिवर्तन बाजार दर पर परिवर्तित किए जाते हैं।

27. किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्रत्युत्तर नहीं दिया है और प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं। उक्त परिस्थिति और किसी चीनी निर्यातक कंपनी द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था पूर्वानुमान के खंडन की अनुपस्थिति में, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में चीन जन गण को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश मानना उचित समझा है और चीन जन गण के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के साथ कार्रवाई का प्रस्ताव किया है।

चीन जन गण के लिए सामान्य मूल्य निर्धारण

28. सामान्य मूल्य का कच्ची सामग्री और व्यवहार्यता के सर्वोत्तम प्राप्त प्रयोक्ता मानदंडों को अपना कर तैयार किया गया है। मुख्य कच्ची सामग्री अर्थात् मेथानॉल और कास्टिक सोडा आई का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अपनाया गया है जबकि लागत के अन्य कारकों को घरेलू उद्योग के लागत ढांचे के अनुसार अपनाया गया है। चूंकि इस मामले में कोई वित्तीय लागत नहीं थी, डीजीएडी पद्धतियों के अनुसार, उत्पादन की लागत पर 5 प्रतिशत का मार्जिन उपलब्ध कराया गया है।

निर्यात कीमत का निर्धारण

29. संबद्ध देश से किसी भी निर्यातक ने निर्यात मूल्य का विवरण देते हुए कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। अतः, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस सौदा-वार डाटा के आधार पर चीन जन गण के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य निर्धारित किया है। चीन जन गण से सभी निर्यातकों के संबंध में एक्स-कैक्ट्री स्तर पर भारित औसत निवल निर्यात कीमत समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, एफओबी कीमत, पत्तन व्यय और अंतर्देशीय माल-भाड़े के लिए उचित समायोजन करने के बाद निर्धारित की गई है। सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के बाद निर्धारित की है, जैसा कि पाटन मार्जिन सारणी में उल्लेख किया गया है।

पाटन मार्जिन का निर्धारण

30. भारत को निर्यात मूल्य की (प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत सभी समायोजनों को घटाकर) पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए सामान्य मूल्य के साथ तुलना की गई है। संबद्ध देश से सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए पीओआई के दौरान पाटन मार्जिन नीचे सारणी में उपलब्ध कराए गए अनुसार निर्धारित किया गया है:

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	मूल्य
1	सामान्य मूल्य	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	****
2	निर्यात कीमत	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	****
3	पाटन मार्जिन	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	****
4	पाटन मार्जिन %	रेंज	20%-30%

च. क्षति और सांयोगिक लिंक

च.1 अन्य संबद्ध पक्षकारों के विचार

क्षति और सांयोगिक संबंध के बारे में किसी भी आयातक, प्रयोक्ता और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कोई टिप्पणी या निवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

च.2 घरेलू उद्योग के विचार

घरेलू उद्योग ने क्षति और सांयोगिक संबंध के बारे में निम्नानुसार निवेदन किया है:

- i. आयात अभी भी जारी है और निम्न तथा पाटित कीमतों पर रिपोर्ट किए जा रहे हैं।
- ii. चीन से आयातों में आधार वर्ष 2012-13 की तथा तत्कालीन पूर्ववर्ती वर्ष 2014-15 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- iii. पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में उल्लेखनीय रूप से कटौती कर रहे हैं।
- iv. आयातों की उतराई कीमत न केवल घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, बल्कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और गैर-क्षतिकारक कीमत से भी कम है।
- v. पीओआई के दौरान पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों सकारात्मक और उल्लेखनीय है।
- vi. संबद्ध देश से तथा अन्य स्रोतों से लगातार पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का उन्मूलन करेगा और कीमतों में वृद्धि को रोकेंगा।
- vii. घरेलू उद्योग के निष्पादन ने उत्पादन और क्षमता उपयोग की शर्तों में सुधार दर्शाया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग कुल लाभ प्राप्त करने के योग्य है।
- viii. घरेलू उद्योग की वृद्धि कुछ मानदंडों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभों, नकद लाभों और निवेशों पर लाभ की शर्तों में सकारात्मक है। तथापि, बिक्री और बाजार शेयर ने मांग में वृद्धि के बावजूद आशा के अनुसार सुधार नहीं दर्शाया है।
- ix. पिछली जांच के समय प्रभावी परिस्थितियां आज तक भी प्रभावी है। परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जो सुझाती है कि पाटन की उस खराब स्तर पर पुनरावृत्ति नहीं होगी जिस पर वह मूल जांच के समय था।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

31. प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न निवेदनों का उल्लेख करता है।
32. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-II में यह उपबंध है कि क्षति निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति की ओर इंगित करते हैं, "..... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर इनका प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए है....." कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, इस बात पर विचार करना आवश्यक समझा गया कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में उल्लेखनीय कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभावों से कीमतों में अन्यथा गिरावट आई है या कीमत में होने वाली वृद्धि को रोकता है, जो अन्यथा पर्याप्त रूप से बढ़ गई होती।
33. डब्ल्यूटीओ करार का अनुच्छेद 3.1 और एडी नियमावली के अनुबंध-II में इन दोनों की तथ्यपरक जांच की व्यवस्था की गई है (क) समान उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में पाटित आयातों की मात्रा और कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव, और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव। पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह जांच करना अनिवार्य है कि क्या पाटित आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, चाहे वह समग्र रूप में हो या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है, क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करता है या कीमत में वृद्धि को रोकता है जो अन्यथा रूप से काफी मात्रा में बढ़ गई होती।
34. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II का पैरा (iv) निम्नानुसार बताता है:

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट, सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक

और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

35. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9(क)(5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि वह पहले समाप्त न किया गया हो, ऐसे लागू किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर रद्द हो जाता है, बशर्ते कि यदि समीक्षा में केंद्रीय सरकार की राय है कि ऐसे शुल्क को समाप्त करने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति की संभावना है, यह और पांच वर्षों की अवधि के लिए ऐसे आरोपण की अवधि को बढ़ा सकते हैं और यह बहुोत्तरी की अवधि ऐसे विस्तार के आदेश की तारीख से आरंभ होगी।

36. ऊपर नियमावली के अनुबंध-II (iv) के अनुसरण में भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, प्राधिकारी ने उद्योग की स्थिति पर होने वाले सूचकांकों पर विचार किया है, जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की प्रमाणा, भंडार, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन का परिमाण और मार्जिन आदि।

37. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न निवेदनों के फलस्वरूप प्राधिकारी ने संबद्ध देश से आयातों के कारण पाटन और क्षति के संभावित पहलुओं की जांच करने के लिए कार्रवाई करने से पूर्व घरेलू उद्योग को हुई वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच करने के लिए कार्रवाई की है।

i. मांग का आंकलन

38. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच, मांग या भारत में उत्पादन की प्रत्यक्ष खपत को सभी स्रोतों से भारतीय उत्पादकों और आयातों की घरेलू बिक्रियों के जोड़ के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है:

देश में मांग

विवरण	यूओएम	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई*
मांग – कैप्टिव को छोड़कर					
संबद्ध देश – चीन	मी. टन	906	2,170	532	2,013
एडीडी को लागू करने वाले देश	मी. टन	3,997	3,046	4,069	2,270
अन्य देश	मी. टन	9,626	10,084	8,944	15,103
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. टन	6,150	6,848	7,172	7,161
अन्य भारतीय उत्पादक	मी. टन	2,592	2,592	3,293	3,293
कुल मांग	मी. टन	23,271	24,740	24,010	29,840
मांग – कैप्टिव सहित	यूओएम				
संबद्ध देश – चीन	मी. टन	906	2,170	532	2,013
एडीडी को लागू करने वाले देश	मी. टन	3,997	3,046	4,069	2,270
अन्य देश	मी. टन	9,626	10,084	8,944	15,103
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. टन	6,195	6,905	7,238	7,235
अन्य भारतीय उत्पादक	मी. टन	5,400	5,400	6,720	6,720
कुल	मी. टन	26,124	27,605	27,503	33,340
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	105	128

39. प्राधिकारी ने टिप्पणी की है कि क्षति की अवधि में एशियन पेंट्स द्वारा कैप्टिव खपत के सहित और उसके बिना विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है।

ii. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

आयात मूल्य और बाजार हिस्सा

40. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में पाटित आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, चाहे वह समग्र रूप में हो या उत्पादन अथवा उपभोग के सापेक्ष में। संबद्ध देश से संबद्ध सामान के आयातों की मात्रा का निम्नानुसार विश्लेषण किया गया है:

विवरण	यूओएम	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई*
आयात मूल्य					
संबद्ध देश – चीन	मी. टन	906	2,170	532	2,013
एडीडी को लागू करने वाले देश	मी. टन	3,997	3,046	4,069	2,270
अन्य देश	मी. टन	9,626	10,084	8,944	15,103
कुल आयात	मी. टन	14,529	15,300	13,545	19,386
खपत (कैप्टिव सहित)	मी. टन	26,124	27,605	27,503	33,340
खपत (कैप्टिव को छोड़कर)	मी. टन	23,271	24,740	24,010	29,840
घरेलू उद्योग का उत्पादन (कैप्टिव सहित)	मी. टन	7,196	6,889	6,880	7,358
के संबंध में संबद्ध आयात					
कुल आयात	%	6%	14%	4%	10%
खपत (कैप्टिव सहित)	%	3%	8%	2%	6%
खपत (कैप्टिव को छोड़कर)	%	4%	9%	2%	7%
उत्पादन (कैप्टिव सहित)	%	13%	32%	8%	27%
उत्पादन (कैप्टिव को छोड़कर)	%	13%	32%	8%	28%

41. यह नोट किया गया है कि क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि हुई है और समग्र रूप में यह अभी भी उल्लेखनीय है और पाटित आयातों पर है। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी शुल्क की विद्यमानता के बावजूद क्षति अवधि के दौरान उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध आयातों में भी वृद्धि हुई है। प्राधिकारी ने यह भी टिप्पणी की है कि डीआई ने पूरी क्षमता पर प्रचालन किया है जो दर्शाता है कि मांग और आपूर्ति के अंतर को देखते हुए आयात अनिवार्य है। किंतु ऐसे आयात पाटित प्रक्रिया पर है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

iii. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

क. कीमत कटौती

42. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में भारी कटौती की गई है अथवा ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करता है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकता है जो अन्यथा काफी मात्रा में बढ़ गई होती। इस संबंध में, उत्पाद का उतराई मूल्य और व्यापार के समान स्तर पर सभी छूटों और करों को घटाकर, घरेलू उद्योग के औसत बिक्री मूल्य के बीच तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतें एक्स-फैक्ट्री स्तर पर निर्धारित की गई थी।

43. कीमत कटौती का आकलन जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयातों की उतराई कीमत की भारत में घरेलू बिक्री कीमत के साथ तुलना कर किया गया है। यह देखा गया है कि पाटनरोधी शुल्क के बिना आयातों की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना में कम है और इसका परिणाम महत्वपूर्ण कीमत कटौती में होता, यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने की अनुमति दी जाती, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	यूओएम	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
निवल बिक्री कीमत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	108	109	118
आधार कीमत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	103	113	112
एडीडी के बिना कीमत कटौती	रु./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	150	72	162
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
रेंज		5-15%	10-20%	5-15%	10-20%

ख. कम कीमत पर बिक्री

44. प्राधिकारी ने टिप्पणी की है कि कम कीमत पर बिक्री क्षति के आकलन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। गैर-क्षतिकारक कीमतें तैयार की गई हैं और कम कीमत पर बिक्री के सीमा तक पहुँचने के लिए संबद्ध वस्तुओं के उतराई मूल्य के साथ उनकी तुलना की गई है। पीओआई में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसरण में, पीओआई के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत को ध्यान में रखते हुए गैर-क्षतिकारक कीमत निर्धारित की गई है।

विवरण	डॉलर यूएसडी/मी. टन
क्षतिरहित कीमत	****
आधार मूल्य	****
क्षति मार्जिन	****
क्षति मार्जिन % रेंज	10-20

45. यह देखा गया है कि चीन से संबद्ध वस्तुओं की उतराई कीमत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित एनआईपी की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम है।

ग. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

46. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का ह्रास या न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव उल्लेखनीय सीमा तक कीमतों का दमन करने के लिए है या मूल्य वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा तक बढ़ जाता। प्राधिकारी ने क्षति अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तन पर विचार किया है। स्थिति नीचे सारणी में दर्शाई गई है:

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई*
बिक्री की लागत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	113	100
बिक्री कीमत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	109	118
आधार कीमत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	113	112

47. यह देखा गया है कि जबकि बिक्री की लागत में क्षति की अवधि में गिरावट आई है, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है। हालांकि, पाटनरोधी शुल्क के बिना आयातों की उतराई कीमत बिक्री कीमत साथ ही घरेलू उद्योग की बिक्री की कीमत से भारी मात्रा में कम है, जिससे पाटनरोधी शुल्कों के उत्पादन के मामले में कीमत दमन/हास हो सकता है।

iv. घरेलू उद्योग का आर्थिक पैरामीटर

48. एडी नियमावली के अनुबंध-II में यह उपबंध है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की उद्देश्यात्मक जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, एडी नियमों में आगे व्यवस्था की गई है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर भार डालने वाले सभी संगत और आर्थिक कारकों और सूचकांकों की जांच उद्देश्यपूर्ण है और इसमें निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए जिसमें बिक्री, लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेशों पर लाभ या क्षमता उपयोग, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेशों को जुटाने की क्षमता शामिल है।

49. तदनुसार, घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों का यहां नीचे विश्लेषण किया गया है।

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

50. उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार था:

विवरण	यूओएम	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई*
क्षमता	मी. टन	7,000	7,000	7,000	7,000
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन	मी. टन	6648	6,889	6,880	7,358
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	103	111
क्षमता उपयोग	%	95%	98%	98%	105%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	103	111
घरेलू बिक्री	मी. टन	6,150	6,848	7,172	7,161
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	117	116

51. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की क्षमता समग्र क्षति अवधि के दौरान स्थिर बनी रही है। उत्पादन और बिक्री के रूप में घरेलू उद्योग के निष्पादन में पाटित आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के परिणामस्वरूप सुधार हुआ है।

ख. मांग में बाजार हिस्सा

52. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभावों की निम्नानुसार जांच की गई है:

बाजार हिस्सा (कैप्टिव सहित)	यूओएम	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
संबद्ध देश - चीन	%	3%	8%	2%	6%
एडीडी को लागू करने वाले देश	%	15%	11%	15%	7%
अन्य देश	%	37%	37%	33%	45%
घरेलू उद्योग	%	24%	25%	26%	22%
अन्य भारतीय उत्पादक	%	21%	20%	24%	20%
कुल	%	100%	100%	100%	100%
बाजार हिस्सा (कैप्टिव को छोड़कर)					

संबद्ध देश- चीन	%	4%	9%	2%	7%
एडीडी को लागू करने वाले देश	%	17%	12%	17%	8%
अन्य देश	%	42%	41%	37%	50%
घरेलू उद्योग	%	26%	28%	30%	24%
अन्य भारतीय उत्पादक	%	11%	10%	14%	11%
कुल	%	100%	100%	100%	100%

53. यह देखा गया है कि आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में लगी आई है जबकि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। अन्य भारतीय उत्पादकों का बाजार हिस्सा क्षति अवधि के दौरान समान स्तर पर बना रहा है। इसके अतिरिक्त, एडीडी लागू करने वाले अन्य देशों के बाजार हिस्से में भी क्षति अवधि के दौरान कमी आई है, जबकि अन्य देशों (एडीडी लागू न करने वाले देश) के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। सकारात्मक कीमत कटौती और चीन के बाजार हिस्से में वृद्धि पर विचार करते हुए, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि चीन जन गण से पाटित आयातों के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।

ग. लाभ/हानि, नकदी प्रवाह, निवेश पर लाभ

54. लाभ, निवेशों पर लाभ और नकदी प्रवाह के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
बिक्री की लागत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	113	100
बिक्री कीमत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	109	118
लाभ/(हानि)	रु./किग्रा.	(***)	(***)	(***)	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-128	-159	90
लाभ/(हानि)	रु. लाख	(***)	(***)	(***)	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-143	-186	105
नकद लाभ	रु. लाख	(***)	(***)	(***)	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-153	-204	147
ब्याज और कर पूर्व लाभ	रु. लाख	(***)	(***)	(***)	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-141	-182	103
नियोजित पूंजी पर लाभ	%	(***)	(***)	(***)	***
रेंज		-(10-20%)	-(20-30%)	-(30-40%)	10-20%

55. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग बाजार में पाटित आयातों की उपस्थिति के कारण 2014-15 तता हानि उपगत कर रहा था। पीओआई में घरेलू उद्योग को कुछ लाभ हुआ है। इसी प्रकार, 2014-15 तक लगातार हानियों के पश्चात

पीओआई में ब्याज, नकद लाभ और निवेशों पर वापसी से पहले लाभ सकारात्मक हुआ है, लेकिन नियोजित पूंजी पर लाभ 22 प्रतिशत की बेंचमार्क वापसी से कम है।

घ. मालसूची

56. घरेलू उद्योग के साथ मालसूची निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
औसत स्टॉक	मी. टन	226	478	257	53
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	203	109	22

57. घरेलू उद्योग के पास मालसूची में 2013-14 में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, 2014-15 में इसमें गिरावट आई और पीओआई में दोबारा वृद्धि हुई।

ङ. उत्पादकता

58. नीचे दी गई जानकारी, प्राधिकारी ने टिप्पणी की है कि दैनिक, साथ ही, प्रति कर्मचारी उत्पादकता की शर्तों में पीओआई के दौरान उत्पादकता में वृद्धि हुई है, जो उत्पादन की विकास के अनुरूप है:

विवरण	यूओएम	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
उत्पादकता	प्रति दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	103	111
उत्पादकता	प्रति कर्मचारी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	102	109

च. रोजगार और मजदूरी

59. नीचे दी गई सारणी से यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान रोजगार का स्तर समान स्तर पर बना रहा है। हालांकि, 2013-14 के दौरान अदा की गई मजदूरी में वृद्धि हुई और पीओआई में इसमें फिर गिरावट आई है।

विवरण	यूओएम	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	102	102
मजदूरी	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	98	94
मजदूरी	रु./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	103	86

छ. पाटन का परिमाण

60. संबद्ध देश से उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में निर्धारित पाटन मार्जिन महत्वपूर्ण है।

ज. वृद्धि

61. प्राधिकारी ने नीचे दी गई सारणी से यह नोट किया है कि लागू किए गए पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के परिणामस्वरूप जांच की अवधि के दौरान मात्रा और कीमत, दोनों पैरामीटरों के रूप में सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है।

वृद्धि	यूओएम	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
उत्पादन	%	--	4%	0%	7%
घरेलू बिक्री मात्रा	%	--	11%	5%	-
क्षमता उपयोग	%	--	3%	0%	7%
घरेलू बिक्री कीमत	%	--	***	***%	***%
कर पूर्व लाभ	%	--	(***)	(***)	***
नकद लाभ	%	--	(***)	(***)	***
नियोजित पूंजी पर निवेश (एनएफए आधारित)	% रेंज	--	-5 से -15%	-5 से -15%	35-45%

झ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

62. प्राधिकारी ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है। तथापि, पाटन जारी है और यह पूंजी जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता को प्रभावित करेगा।

ञ. पाटन का स्तर और पाटन मार्जिन

63. यह देखा गया है कि देश में संबद्ध देशों से आयात का आगमन हो रहा है और पाटन का मार्जिन उल्लेखनीय है।

ट. घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक

64. संबद्ध देश से आयात कीमतों की जांच, मूल्य ढांचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्द्धा, पाटित आयातों के अतिरिक्त अन्य कारक जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, आदि दर्शाते हैं कि संबद्ध देश से आयातित सामग्री का उतराई मूल्य बिक्री मूल्य से कम हैं और घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत भारतीय बाजार में उल्लेखनीय कीमत कटौती के साथ ही कम कीमत पर बिक्री का कारण बन सकती हैं। भारतीय उत्पादकों की कीमत के लिए बेंचमार्क विभिन्न स्रोतों, संबद्ध देशों सहित, से आयातित कीमतें हैं। इस उत्पाद का कोई संभव विकल्प नहीं है। अतः घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात का उतराई मूल्य है।

ड. क्षति पर निष्कर्ष

65. घरेलू उद्योग की क्षति से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों की जांच और विश्लेषण करने के बाद प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि पाटन-रोधी शुल्कों के लागू होने के बावजूद चीन जनवादी गणराज्य से आयात पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं। पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक कटौती कर रहे हैं। आयातों की पहुंच कीमत ने केवल घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, बल्कि यह घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और और क्षति रहित कीमत से भी बहुत कम है। जांच अवधि में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों ही सकारात्मक और बहुत अधिक हैं। घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन ने उत्पादन और बिक्रियों की मात्रा के रूप में सुधार दर्शाया है। साथ ही घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन ने कीमत प्राचलों के रूप में भी कुछ सुधार दर्शाया है क्योंकि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि में कुछ लाभ अर्जित किया है।

च. अन्य ज्ञात कारक और कारणात्मक संबंध

66. प्राधिकारी ने इसकी जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है, जो कि निम्नानुसार है:-

- (1) **पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और मूल्य:** चीनी ताईपाई, रूस और यूरोपीय यूनियन (स्वीडन को छोड़ कर) से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लग रहा है। सऊदी अरब और स्वीडन को छोड़ कर अन्य सभी देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा या तो बहुत कम है अथवा वे अधिक कीमतों पर होते हैं और उनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है। प्राधिकारी ने पहले सऊदी अरब के खिलाफ पाटन-रोधी जांच शुरू की थी और बाद में उस जांच को इसलिए समाप्त कर

दिया गया था क्योंकि उसमें पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से कम पाया गया था। वर्ष 2011 में स्वीडन से आयातों पर लगने वाले पाटन-रोधी शुल्क को रद्द कर दिया गया था।

- (2) **मांग में संकुचन:** विचाराधीन उत्पाद की मांग ने सकारात्मक संवृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई है। मांग में संभावित कमी होने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है।
- (3) **खपत के पैटर्न में परिवर्तन :** विचाराधीन उत्पाद से संबंधित खपत पैटर्न में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए खपत में परिवर्तन होने को घरेलू उद्योग की क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है।
- (4) **विदेशी और घरेलू उत्पादों के बीच व्यापारिक प्रतिबंधित पद्धतियां तथा प्रतिस्पर्धा:** प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी कोई व्यापारिक प्रतिबंधित पद्धति नहीं है, जिसके कारण रेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।
- (5) **प्रोद्योगिकी में विकास:** प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उत्पादन की प्रोद्योगिकी में किसी भी प्रकार का कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है।
- (6) **निर्यात निष्पादन:** घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन के संबंध में यथा संभव घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन और क्षति की जांच की गई है। इसलिए घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में संभावित गिरावट आना घरेलू उद्योग की क्षति का संभावित कारण नहीं हो सकता है।
- (7) **घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन:** प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों के कार्य-निष्पादन ने प्राधिकारी द्वारा किए गए घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन को प्रभावित नहीं किया है। प्राधिकारी ने केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सूचना का ही विश्लेषण किया है।
- (8) **उत्पादकता:** प्राधिकारी नोट करते हैं कि उद्योग की उत्पादकता में वैसी ही प्रवृत्ति रही है जैसी प्रवृत्ति उत्पाद की थी और उसमें वृद्धि हुई है। उत्पादकता में गिरावट आना घरेलू उद्योग की क्षति का कारण नहीं है।

67. प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि उपरोक्त सूचीबद्ध ज्ञात कारकों से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन के विश्लेषण से पता चलता है कि पाटन-रोधी शुल्क लगने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है। तथापि, संबद्ध देश से पाटित कीमतों पर अत्यधिक मात्रा में आयात देश में प्रवेश कर रहे हैं। प्राधिकारी का यह विचार है कि यदि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है, तो पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति होगी।

छ. क्षति पर निष्कर्ष और उनका कारण

68. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद भी संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा, समग्र रूप से और भारत में खपत और उत्पादन के संबंध में बहुत अधिक है। यह नोट किया जाता है कि उत्पादन, क्षमता, उपयोग, घरेलू विक्रियों और बाजार के हिस्से जैसे सभी आर्थिक प्राचलों के रूप में घरेलू उद्योग की संवृद्धि सकारात्मक रही है। जांच अवधि में घरेलू उद्योग ने लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया था। तथापि, आयात निरंतर पाटित कीमतों में प्रवेश कर रहा है और पाटन-रोधी शुल्क लागू नहीं होने की स्थिति में इसके कारण कीमतों में अत्यधिक कटौती होगी और कम कीमत पर विक्रियां होंगी। यह नोट किया जाता है कि फिर भी संबद्ध वस्तुओं का निरंतर पाटन हो रहा है। इसलिए प्राधिकारी ने पाटन के निरंतर जारी रहने और उसके घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन पर परिणामी प्रभाव का विस्तार से विश्लेषण नीचे दिए गए पैराओं में किया है।

ज. पाटन और क्षति के निरंतर जारी रहने और उनकी पुनारुति होने की संभावना

69. प्राधिकारी ने यह देखा है कि यह निर्णायक समीक्षा जांच है और इस जांच का संकेन्द्रण इस तथ्य की जांच करना है कि यदि वर्तमान क्षति नहीं भी होती है, तो क्या पाटन-रोधी शुल्क समाप्त कर दिए जाने से पाटन और परिणामी क्षति होने की संभावना है। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध आयात, घरेलू बाजार में पाटित और क्षति कीमतों पर निरंतर प्रवेश कर रहे हैं।

झ.1. घरेलू उद्योग के निवेदन

70. पाटन और क्षति के निरंतर जारी रहने और उनकी पुनारुति होने की संभावना के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) विगत जांच और वर्तमान याचिका में निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन सकारात्मक और अत्यधिक है। इनसे स्पष्ट पता चलता है कि पाटन-रोधी शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन की संभावना और उसकी परिणामी क्षति होगी। विगत जांच में प्राधिकारी ने सहयोगी और असहयोगी दोनों निर्यातकों के लिए 50-60% की सीमा में पाटन मार्जिन निर्धारित किया था। वर्तमान जांच में भी पाटन मार्जिन अत्यधिक है।
- (2) संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों के पास अत्यधिक उत्पादन क्षमताएं विद्यमान हैं। चीन में "पेनोटेरीथ्रिटोल" का उत्पादन लगभग 3.4 लाख मी.टन होता है। हुबेई हिहुआ ग्रुप एलएलसी नामक सबसे बड़ा उत्पादक इसका 1.2 लाख मी.टन का उत्पादन करता है। चीन की घरेलू बिक्रियों में हुबेई हिहुआ ग्रुप एलएलसी का हिस्सा 70% है।
- (3) विदेशी उत्पादक अपना ध्यान निर्यातों पर संकेन्द्रित करते हैं। तृतीय देशों में अत्यधिक पाटन किया जाता है। पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में ऐसी संभावना है यह निर्यातक पाटित कीमतों पर भारत में अपने निर्यात बढ़ा देंगे।
- (4) याचिकादाता ने चीन के सीमा-शुल्क विभाग के अनुसार तृतीय देशों को चीन से निर्यातों का विश्लेषण किया है और देश-वार आधार पर तृतीय देश के पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण किया है। इससे यह देखा जा सकता है कि चीन से पाटन और क्षति कीमतों पर विभिन्न गंतव्य स्थानों को अत्यधिक मात्रा में निर्यात किए जा रहे हैं।
- (5) भारतीय बाजार अत्यधिक कीमत संवेदी है। ग्राहक अपनी अधिप्राप्ति करने का निर्णय करने में कीमत को सर्वाधिक प्राथमिकता देते हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय बाजार में संबद्ध देश से इतनी कम कीमत पर आयातों की उपलब्धता से निश्चय ही घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस तथ्य की संपुष्टि, संबद्ध देश द्वारा अपनाई जा रही दीर्घावधिक पाटन की पद्धति से हो जाती है।
- (6) जिन कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं का आयात किया जा रहा है, वे उस कीमत से पर्याप्त रूप से कम हैं, जिस पर उसे घरेलू बाजार में बेचा जाता है। इसलिए शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में निर्यातक अपने उत्पादन को भारतीय बाजार में सरणीबद्ध करने के प्रति अग्रसर होंगे क्योंकि उनके पास पहले से ही अत्यधिक उत्पादन क्षमताएं विद्यमान हैं और वास्तव में वे संबद्ध वस्तुओं को पर्याप्त रूप से कम कीमतों पर तृतीय देशों को बेच रहे हैं।

अ.2 उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन

71. इस संबंध में किसी भी उत्पादक, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई निवेदन नहीं किया है।

अ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

72. प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के निरंतर जारी रहने और उनकी पुनारवृत्ति होने की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की जांच की है। निम्नोक्त विश्लेषण से पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति के निरंतर जारी रहने और उनकी पुनारवृत्ति होने की संभावना का पता चलता है।

(1) वर्तमान और विगत पाटन का स्तर:

73. विगत जांच में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए पाटन मार्जिन और अब मूल्यांकित पाटन मार्जिन को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट पता चलता है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटित कीमतों पर निर्यातों के निरंतर जारी रहने की संभावना है। जहां तक कि पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद भी पाटित आयातों में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त क्षति अवधि में अत्यधिक कीमत कटौती होने और कम कीमत पर बिक्री होने को ध्यान में रखते हुए पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में आयातों की मात्रा में और वृद्धि होने की संभावना है।

(2) भारतीय बाजार का कीमत आकर्षण:

74. चीन जनवादी गणराज्य से जिस कीमत पर संबद्ध वस्तुओं के निर्यात भारत को किए जा रहे हैं, वह पाटन के निरंतर जारी रहने/गहन होने की संभावना की एक सूचक है। भारत में पाटन रोधी शुल्क लगे होने और नहीं लगे होने की दोनों स्थितियों में वर्तमान पहुंच कीमत से जांच अवधि में घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती हुई है। इस प्रकार पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में भारतीय कीमतें चीन के उत्पादकों को पाटित कीमतों पर अपने निर्यात को गहन बनाने के लिए बहुत आकर्षित करेंगी और ऐसी प्रबल संभावना है कि उपभोक्ता बड़े पैमाने पर चीन से संबद्ध वस्तुओं के आयात करने के प्रति उन्मुख होंगे।

(3) चीन के निर्यातकों का निर्यातोन्मुखीकरण:

75. विभिन्न देशों को चीन से निर्यात के संबंध में याचिकादाता द्वारा प्रदत्त की गई सूचना का विश्लेषण किया गया है। यह नोट किया जाता है कि विभिन्न गंतव्य देशों को चीन से अत्यधिक मात्रा में निर्यात, पाटन और क्षति कीमतों पर किए गए हैं। शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में संबद्ध देश के निर्यातकों के पाटित कीमतों पर भारत को अपने निर्यात बढ़ाने की संभावना है।

(4) उत्पाद और भारतीय बाजार के कीमत संवेदी होने के रूप में घरेलू उद्योग की अरक्षितता:

76. भारतीय बाजार अत्यधिक कीमत संवेदी है। उत्पादक अपनी अधिप्राप्ति का निर्णय, मुख्यतया उत्पाद की कीमत के आधार पर लेते हैं। इसलिए भारतीय बाजार में संबद्ध देश से कम कीमत पर होने वाले आयातों की उपलब्धता से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस तथ्य की संपुष्टिसंबद्ध देश द्वारा अपनाई जा रही दीर्घावधिक पाटन पद्धति से होती है। इस प्रकार पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन होने और घरेलू उद्योग पर उसकी परिणामी क्षति होने की संभावना है।

(5) चीन में अत्यधिक उत्पादन क्षमता का होना:

77. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों के पास अत्यधिक उत्पादन क्षमता विद्यमान है जो कि भारतीय मांग से बहुत अधिक है। इस प्रकार पाटन-रोधी शुल्क समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से पाटित आयातों में उछाल आने की संभावना है।

(6) पाटन और क्षति की संभावना पर निष्कर्ष:

78. पाटन-रोधी शुल्क के निरंतर लागू रहने के बावजूद भी संबद्ध देश से आयातों के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि पाटन-रोधी शुल्क समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को गहन पाटन और उसकी परिणामी क्षति होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया जाता है कि आयात कीमतें घरेलू कीमतों में कटौती करेंगी और उनका घरेलू कीमतों को अत्यधिक ह्रास करने का भी प्रभाव पड़ेगा।

ज. क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

79. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-3 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना, जांच अवधि में क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए संबद्ध देश से निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है और इस प्रकार से आकलित किया गया क्षति मार्जिन निम्नानुसार है:-

विवरण	यूनिट	जांच अवधि
क्षति रहित कीमत	अमरीकी डालर/मी.टन	***
पहुंच मूल्य	अमरीकी डालर/मी.टन	***
क्षति मार्जिन	अमरीकी डालर/मी.टन	***
क्षति मार्जिन	%	***
क्षति मार्जिन	सीमा	10-20

ट. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

80. प्रकटन विवरण के उत्तर में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

ट.1. घरेलू उद्योग के निवेदन:

81. घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निवेदन किए हैं:-

- (1) प्राधिकारी द्वारा क्षति रहित कीमत, निर्यातकों की सत्यापन रिपोर्टों (उनका अगोपनीय वृत्तान्त) और प्राधिकारी द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजे गए पत्रों और उनके उत्तरों जैसे दस्तावेज प्रदान किए जाएं।

- (2) संबद्ध वस्तुओं पर निर्धारित मात्रा में (शुल्क के रूप में) पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाए। इसका कारण यह है कि विचाराधीन उत्पाद पर निर्धारित मात्रा में पाटन-रोधी शुल्क लागू हो रहा है और इसलिए इसे निरंतर जारी रखा जाए।
- (3) शुल्क अमरीकी डालरों में लगाया जाना चाहिए।

ट.2. हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन:

82. इस संबंध में किसी भी उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कोई निवेदन नहीं किया है।

ट.3. प्राधिकारी द्वारा जांच:

83. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन-पश्चात किए गए निवेदन/की गई टिप्पणियां पहले किए गए निवेदनों की पुनरावृत्ति मात्र हैं, जिनकी पहले से ही उपयुक्त रूप से जांच कर ली गई है और वर्तमान जांच परिणाम में संबद्ध पैराओं में निदान कर दिया गया है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए नए मुद्दों पर आगे विचार करते हैं जो कि निम्नानुसार हैं:-

- (1) क्षति रहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण करने से संबंधित घरेलू उद्योग के निवेदनों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-3 के अंतर्गत क्षति रहित कीमत का परिकलन करने के व्यापक दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं और वर्तमान जांच में क्षति रहित कीमत का निर्धारण करते समय उनको अपनाया गया है।
- (2) शुल्क के रूप के बारे में घरेलू उद्योग के निवेदन के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह अधिदेश है कि वह आरोपित पाटन के विद्यमान होने, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करे और पाटन-रोधी शुल्क की ऐसी पर्याप्त मात्रा की सिफारिश करे, जिसे यदि लगाया जाता है, तो वह घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा। तदनुसार मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पाटन-रोधी उपाय के रूप की उपयुक्तता पर निर्णय लिया जाता है।

ड. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

84. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्यतया पाटन की अनुचित व्यावहारिक पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में ऐसे खुले और उचित प्रतिस्पर्द्धा का वातावरण बहाल किया जा सके, जो कि देश के सामान्य हित में हो। पाटन-रोधी उपाय करने से किसी भी तरह से संबद्ध देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए इनसे उपभोक्ताओं को उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

85. यह माना जाता है कि पाटन-रोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं से विनिर्मित उत्पाद की कीमत स्तर पर इस उत्पाद की प्रतिस्पर्द्धा के संबंध में कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटन-रोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्द्धा कम नहीं होगी, विशेषकर यदि लगाए जाने वाले पाटन-रोधी शुल्क की राशि उतनी ही रहे, जो कि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए आवश्यक हो। इसके विपरीत पाटन-रोधी उपाय करने से पाटन की पद्धतियों द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने की अनुचित प्रक्रिया समाप्त होगी, घरेलू उद्योग में होने वाली गिरावट रुकेगी तथा उपभोक्ताओं की व्यापक पसंद की संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

ठ. सिफारिशें

86. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों और उनमें उठाए गए मुद्दों और तर्कों की जांच करने तथा इस अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी के समक्ष रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों तथा पाटन और परिणामी क्षति और पाटन के जारी रहने/पुनरावृत्ति होने/पाटन और क्षति के गहन होने की संभावना को ध्यान में रखने के बाद प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि:-

- (1) चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध उत्पाद के निरंतर पाटन होने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।
- (2) आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और कम कीमत पर बिक्री हो रही है।
- (3) पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप निरंतर पाटन होने, उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

87. तदनुसार प्राधिकारी सीमा-शुल्क प्रशुल्क वर्गीकरण अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत आने वाले अथवा चीन जनवादी गणराज्य में शुरू होने वाले अथवा वहां से निर्यातित पलेटेथ्रिटों के आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से संशोधित पाटन-रोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करते हैं। इस पाटन-रोधी शुल्क की राशि, नीचे तालिका के कालम 9 में निर्दिष्ट राशि के बराबर होगी।

शुल्क तालिका

क्रमांक	उप-शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	विनिर्देशन	उदगम का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	2905	पेनटेरीथ्रिटोल	कोई	चीन	चीन	कोई	कोई	185.15	मी.टन	अम.डॉ.
2.	2905	पेनटेरीथ्रिटोल	कोई	चीन	कोई	कोई	कोई	185.15	मी.टन	अम.डॉ.
3.	2905	पेनटेरीथ्रिटोल	कोई	कोई	चीन	कोई	कोई	185.15	मी.टन	अम.डॉ.

आगे की प्रक्रिया

88. इस अधिसूचना के विरुद्ध कोई भी अपील केन्द्र सरकार द्वारा इसे स्वीकृत किए जाने के बाद सीमा-शुल्क अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जाएगी।

डॉ. इंद्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI- DUMPING & ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2017

(Final Findings)

Subject: Final Findings in the Sunset Review of Anti-dumping duty imposed on the imports of Pentaerythritol originating in or exported from China PR.

F. No. 15/01/2016-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

A. BACKGROUND OF THE CASE

- Whereas, having regard to the above Act and the Rules, the Designated Authority (hereinafter referred to as Authority) initiated an anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from China PR and Sweden, vide notification No. 14/16/2004-DGAD dated February 4, 2005. The Preliminary Findings were notified on August 5, 2005. The Authority notified final findings on February 2, 2006 recommending definitive anti-dumping duty on the imports of Pentaerythritol originating in or exported from China and Sweden. The definitive anti-dumping duties on the subject goods imported from subject countries were imposed by the Department of Revenue vide notification No. 37/2006 dated 20.04.2006.
- The Authority initiated sunset review investigations vide Notification No. 15/3/2010-DGAD dated 26th March 2010. The Authority recommended continued imposition of definitive anti dumping duties on imports from China PR vide notification No.15/3/2010-DGAD, dated the 25th March, 2011 and

Ministry of Finance extended definitive anti-dumping duty vide notification No. 47/2011-Customs, dated the 14th June, 2011 on all imports of subject goods originating in or exported from China PR. However, anti dumping duties on imports from Sweden were revoked by the Authority in the sunset review.

3. And, notwithstanding the above provision, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
4. And whereas, M/s Kanoria Chemicals and Industries Limited (hereinafter also referred to as “*Petitioner*” or “*Applicant*”) filed an application in the present case before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Act and the Rules for initiation of sunset review anti-dumping investigations concerning imports of Pentaerythritol (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the subject country) and requested for extension of anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.
5. And whereas, the Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the applicant to justify initiation of sunset review investigation issued a public notice vide Notification No. 15/01/2016 – DGAD dated 7th June, 2016. The validity of the *anti-dumping* duty on the imports of the subject goods from the subject country was extended by the Central Government up to 13th June 2017 vide Notification No. 26/2016-Customs (ADD) dated 13th June, 2016.
6. The scope of the present review covers all aspects of the original investigation concerning imports of the above goods, originating in or exported from China PR.

B. PROCEDURE

7. Procedure described below has been followed with regard to this investigation, after issuance of the public notice notifying the initiation of the above investigation by the Authority.
 - i. The Authority notified the Embassy/Representatives of the subject country in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.
 - ii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the embassy of the subject country in India, known producers/exporters from the subject country, known importers/users in India, other Indian producers and the domestic industry as per the addresses made available by the applicants and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.
 - iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.
 - iv. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from China to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from China PR.
 - v. The Authority sent Exporter’s Questionnaire and Market Economy Questionnaire to elicit relevant information to the following known producers/exporters in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - (a) M/s. Hubei Yihua Group Limited Liability Company
 - (b) M/s. Guizhou Crystal Chemical Co. Ltd.
 - (c) M/s. China National Chemicals Construction Corporation
 - (d) M/s Sinochem Jiangsu Import & Export Corporation

(e) M/s Shanxi Sanwei Group Company Ltd.

- vi. In response to the above notification, none of the exporters/ producers has responded or submitted questionnaire responses.
- vii. The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
- (a) Addison Paints & Chemical Ltd.
 - (b) Berger Paints India Limited
 - (c) Century Enka Limited
 - (d) Ciba Specialty Chemicals (India) LT
 - (e) Coates Of India Ltd
 - (f) Decro Paints
 - (g) Dujodwala Paper Chemicals Ltd.
 - (h) Gargi Industries Prop.
 - (i) Goodlass Nerolac Paints Ltd
 - (j) Hardcastle & Waud Mfg Co Limited
 - (k) Hero Dye Chem Industries
 - (l) Hindustan Inks & Resins Ltd.
 - (m) IVP Ltd.
 - (n) Jenson & Nicholson (I) Ltd.
 - (o) Mitsu Inds.Limited
 - (p) Paras Dyes & Chemicals
 - (q) Resin & Pigments
 - (r) Perstorp Chemicals India Pvt Ltd
 - (s) A.V.M. Sales Pvt. Ltd.
 - (t) Alcon Enterprises
 - (u) Chemi Colour Agency
 - (v) Eastcorp International
 - (w) Garware Polyester Ltd.
 - (x) H. R. Trading Co. Pvt. Ltd
 - (y) Leo Chemoplast Pvt. Ltd.
 - (z) Samir Dye Chem
 - (aa) Sanman Trade Impex Pvt. Ltd.
 - (bb) Saraf Chemicals Ltd.
 - (cc) Vibgyor Paints Pvt. Ltd.
 - (dd) Shalimar Paints Ltd.

- viii. None of the importers has filed submissions or response to the Importer's questionnaire.
- ix. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;
- x. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigations, which was received by the Authority. The Authority has, relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions; The transaction wise import data was placed in the public file.
- xi. The Non-injurious Price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-dumping Rules has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xii. The Authority held an oral hearing on 19th September 2016 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance to Rule 6 (6), which was attended by the representatives of domestic industry only. The representatives of domestic industry who presented their views orally at the time of oral hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally.
- xiii. Due to change in the incumbency of the Designated Authority and in line with the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the ATMA case, another oral hearing was conducted by the new Designated Authority on 6th February 2016, which was attended by the representatives of domestic industry only. The representatives of domestic industry who presented their views orally at the time of oral hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally.
- xiv. On the spot verification of the data of the domestic industry was carried out to the extent considered necessary. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of this finding.
- xv. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is April, 2015- March, 2016 (12 months). The examination in the context of injury analysis covers the periods April 2012-March 2013, April 2013-March 2014, April 2014-March 2015 and the POI.
- xvi. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this finding.
- xvii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.
- xviii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.
- xix. In accordance with Rule 16 of the Rules Supra, the essential facts were disclosed by the Authority on 14th March, 2017 to the concerned interested parties. Comments were requested by 20th March, 2017. Comments received on the disclosure statement to the extent considered relevant by the Authority have been considered in this final finding.
- xx. '***' in this final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

- xxi. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs.65.91 = 1 US\$.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1 Views of the Domestic industry

8. The views of the domestic industry are as follows:
- The present review investigation is a sunset investigation. The product involved in the original investigation and in the present sunset review investigation is Pentaerythritol. The product under consideration in the present sunset review is the same as has been held by the Designated Authority in the original investigation. Pentaerythritol is an organic chemical classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. However, scope of the investigation excludes di-pentaerythritol. It is produced and marketed in two grades - technical and nitration. However, there is no material difference found between these two grades and both the grades are produced out of same process. During the production process less than 2% of entire production of Pentaerythritol results into the production of nitration grade whereas more than 97% constitutes as technical grade.
 - Pentaerythritol is used in the manufacture of Alkyd Resin, Resin Esters, Plasticizers, Printing Inks, Synthetic Rubber, Stabilizers for Plastics, Modified drying oils, Detonators, Explosives, Pharmaceuticals, Core oils and Synthetic Lubricants. The subject goods fall under Chapter 29 of the Act under subheading no. 2905.42. However, the customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.
 - There is no difference in the technology employed and the quality of the domestic and imported product. Present investigation is a review investigation. The Designated Authority has examined the issue of product under consideration and like article in the original investigation, which is relied upon.

C.2. Views of the other interested parties

9. None of the importers, consumers, exporters and any other interested party has filed any comment or submissions with regard to product under consideration, and like articles.

C.3. Examination by the Authority

- The product under consideration is Pentaerythritol, an organic compound which finds application in manufacture of Alkyd Resin, Rosin Esters, Plasticizers, Printing Inks, Synthetic Rubber, and Stabilizers for Plastics, Modified Drying Oils, Detonators, Explosives, Pharmaceuticals, Core Oils and Synthetic Lubricants. Pentaerythritol can be of technical grade or nitration grade and both grades are included within the scope of product under consideration and present investigation. Pentaerythritol is classified under Customs sub heading No 2905.42 under chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975.
- The present investigation being a sunset review investigation and anti-dumping duties, as earlier recommended by the Authority, being in force on the imports of the subject goods from the subject country, the Authority considers that the scope of the PUC in the present investigation remains the same as that in the original and subsequent review investigations, as per Rule 2(d) of Anti-Dumping Rules.
- After considering the information on record, the Authority holds that there is no known difference in product under consideration exported from subject country and the product produced by the Indian industry. The subject product produced by the domestic industry is comparable to the Product under consideration in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.
- Thus, the Authority holds that the subject product produced by the applicant domestic industry is like article to the Product under consideration, in accordance with the AD Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Views of the Domestic industry

14. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to scope and standing of the domestic industry:

- i. The petition was filed by M/s. Kanoria Chemicals and Industries Limited as a domestic producer of the product under consideration. There are two producers of Pentaerythritol in the Country. Apart from petitioner, the subject goods are being produced by Asian Paints (India) Ltd. While Asian Paints produces the goods primarily for captive consumption, it has also undertaken some sales in the Indian Market in the relevant period. Further, the production of Asian Paints to the extent of captive consumption should not be included in the eligible production, as this production does not compete with the dumped material supplied by the Foreign Producers or sales made by the Indian Producers.
- ii. Perstorp Chemicals India Pvt. Ltd., named as a producer of the subject goods in previous investigations, (hereinafter referred to as 'Perstorp India') has no domestic production from 2009-10 onwards and is no longer considered an Indian producer of the product under consideration. It has been established in the previously concluded anti-dumping investigations on imports of the product under consideration from other sources that Perstorp India is an importer of the subject goods and procures shipments from its related companies abroad.
- iii. Therefore, M/s. Kanoria Chemicals and Industries Limited is the only eligible domestic producer of the subject goods in India and constitute domestic industry under Rule 2(b) of the Rules, 1995.
- iv. Production of petitioner constitutes a major proportion in Indian Production (both after including and excluding captive consumption by Asian Paints) and therefore, the petitioner should be treated as "domestic industry" within the meaning of the Rules.
- v. The petitioner has not imported the subject goods during the period of investigation, and further, is not related to any exporter or producer of the subject goods in China or any importer or user of the product under consideration in India within the meaning of Rule 2(b).

D.2. Views of the other interested parties

15. None of the producers/exporters/importers/other interested parties has made any submissions in this regard.

D.3. Examination of the Authority

16. Rule 2 (b) of the AD rules defines domestic industry as under:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"

17. The application has been filed by M/s. Kanoria Chemicals and Industries Limited. Other known producer, Asian Paints (India) Ltd. produces the subject goods for captive consumption also.

18. As per the Anti-dumping Rules, the Authority is required to examine whether (a) domestic producers expressly supporting the application account for more than twenty five percent of the total production of the like article by the domestic industry; and (b) the application is supported by those domestic producers whose collective output constitute more than fifty percent of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition to the application. The applicant constitutes 69% of the total domestic production excluding production for captive consumption by Asian Paints; and the applicant constitutes 52% of the total Indian production including production for captive consumption by Asian Paints. Further, the petitioner has not imported the subject goods during the period of investigation, and, is not related to any exporter or producer of

the subject goods in subject country or any importer or user of the product under consideration in India within the meaning of Rule 2(b).

Production excluding captive consumption

	Particulars	UOM	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	Petitioner	MT	6,648	6,831	6,814	7,284
a	Kanoria Chemicals	MT	6,648	6,831	6,814	7,284
2	Other Indian Producer	MT	2,614	2,620	3,257	3,261
3	Total Indian Production	MT	9,262	9,451	10,072	10,546
	Share	UOM	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	Petitioner	%	71.78	72.28	67.66	69.08
2	Kanoria Chemicals	%	71.78	72.28	67.66	69.08
3	Other Indian Producer	%	28.22	27.72	32.34	30.92
4	Total Indian Production	%	100.00	100.00	100.00	100.00

POI: April 15 to March16

Statement of Indian Production including captive

	Particulars	UOM	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	Petitioner	MT	6,648	6,831	6,814	7,284
2	Other Indian Producer	MT	2,592	2,592	3,293	3,293
3	Captive (Petitioner +Other)	MT	2,853	2,866	3,493	3,501
4	Total Indian Production	MT	12093	12,347	13,666	14,152
	Share	UOM	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	Petitioner	%	54.97	55.59	50.11	51.74
2	Other Indian Producer	%	21.44	21.09	24.21	23.39
3	Captive	%	23.59	23.32	25.68	24.87
4	Total Indian Production	%	100	100	100	100

POI: April 15 to March16

19. In view of the above and after due examination, the Authority holds that the applicant satisfies the standing requirements and constitute domestic industry under Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules.

E. Market Economy Treatment (MET), Normal Value, Export Price and Determination of Dumping Margin

20. 'Normal Value' under the Rules -

According to Section 9A (1) (c) of the Customs Tariff Act, 1975 'Normal Value' in relation to an article means: -

comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

E.1 Views of the Domestic industry

21. The domestic industry inter alia submitted as follows:

- a. One of the provisions of Accession protocol has expired on 11th December, 2016. The Designated Authority should proceed with present investigation considering Chinese producers as producers operating in non-market economy conditions due to reasons given below.
- b. The investigation period considered by the Authority in the present case is April 2015 to March 2016 (12 months). The injury investigation period has been considered as the period 2012-13, 2013-14, 2014-15 and POI.
- c. The purpose of fixation of POI is to consider a period when the existence of dumping causing injury is claimed and established. The date of determination is not relevant to the moot question of dumping causing injury to the domestic industry. Since the factum of dumping causing injury to the domestic industry is established based on investigation period, the conditions prevalent during the investigation period alone should be considered relevant, appropriate and necessary for the purpose.
- d. The Chinese producers are required to be treated as non-market economy companies for the reason that the costs and prices in China do not reasonably reflect the market forces. Para 8 to Annexure-I specifies the parameters which should be considered for grant of market economy status. This also implies that unless these conditions are not fulfilled/ satisfied, the Chinese costs and prices cannot be adopted.
- e. The consideration of market economy status is based on parameters prevailing during investigation period. Since the reason for rejection of Chinese costs and prices is distortion in the costs and prices in China due to the factors listed in Para 8 to Annexure-I, petitioner submits that it is the investigation period that is relevant to decide consideration of Chinese producers as market economy companies.
- f. Since Chinese companies have been denied market economy status for the reasons mentioned in Para 8 of Annexure-I till December, 2016, petitioner submits that the Chinese producers are required to be treated as non-market economy companies till such time the investigation period includes the period specified in Accession Treaty protocol.
- g. In the context of rule 2(b), it is well established legal position that the imports by a domestic producer or its relationship with an exporter or importer are examined with reference to the investigation period. If POI alone is relevant for standing purposes, POI alone should be relevant for normal value determination.

- h. Chinese producers are required to be treated as companies operating under non-market economy environment and the Authority may proceed to determine the normal value on the basis of Para 7 of Annexure-I.
- i. Normal value could not be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not publicly available. The petitioner has claimed consideration of normal value on the basis of cost of production in India duly adjusted.
- j. The dumping margin from China is not only significant, but also substantial, thus establishing existence of significant dumping of the product under consideration in India. The import volume of China has remained significant throughout the present injury period, despite anti dumping duty in force.
- k. Considering the production capacities available with Chinese producers and their high export orientation, dumping would continue and even intensify in the event of cessation of anti dumping duty.

E.2. Views of the interested parties

22. None of the importers, consumers, exporters and other interested parties has filed any comment or submissions with regard to dumping margin.

E.3. Examination by the Authority- China as non-market economy

23. Article 15 of China's Accession Protocol provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

- (a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

- (b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*

- (c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*

Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

24. Article 15 implies that provisions of one of the subparagraph shall expire 15 years from date of China's Accession. The provisions of this paragraph expired in 11th Dec., 2016. Since the factum of dumping causing injury to the domestic industry is established based on investigation period, the conditions prevalent during the investigation period alone is relevant, appropriate and necessary for the purpose of present investigation. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is, April 2015 – March, 2016. Since the subparagraph of Article 15 was in existence during the period of investigation, the Authority may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.
25. The Authority notes that in the past three years, China PR has been treated as non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members. China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the Rules.

Examination of Market economy claims

26. As per Paragraph 8, Annexure I to the Anti-Dumping Rules as amended, the presumption of a non-market economy can be rebutted if the exporter(s) from China PR provides information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) in Paragraph 8 and prove to the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from People's Republic of China PR are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether: -
 - a. The decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
 - b. The production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
 - c. Such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms; and
 - d. The exchange rate conversions are carried out at the market rate
27. None of the exporter/producers have responded and filed questionnaire response. In view of the above position and in the absence of rebuttal of non-market economy presumption by any Chinese exporting company, the Authority considers it appropriate to treat China PR as a non-market economy country in the present investigation and proceeds with para-7 of Annexure-I to the Rules for determination of normal value in case of China PR.

Normal value determination for China PR

28. In view of the above, the Authority has determined normal value having regard to para-7 of Annexure-I for the purpose of present investigation. Normal value has been constructed by adopting best achieved consumption norms of raw material and utilities. International rate of key raw material namely methanol and caustic soda lye have been adopted while other elements of cost have been adopted as per domestic

industry's cost structure. As there was no finance cost in this case, a margin of 5% on cost of production has been provided as per DGAD practice.

F. Determination of Export Price

29. None of the exporter from the subject country has provided any information giving details of export price. Therefore, the Authority has determined the export price for producers/exporters of China PR on the basis of the DGCI&S transaction wise data. Accordingly, the weighted average net export price at ex-factory level, in respect of all exporters from China PR has been determined after making the due adjustments for Ocean Freight, Marine Insurance, FOB Price, Port Expenses, and Inland Freight on the basis of best available information as mentioned in the dumping margin table.

G. Determination of Dumping Margin

30. The export price to India (net of all the adjustments accepted by the Authority) has been compared with the normal value to determine dumping margin. The dumping margin during the POI for all exporters/producers from subject country has been determined as provided in the table below:

SN	Particulars	UOM	Value
1	Normal Value	US\$/MT	****
2	Export Price	US\$/MT	****
3	Dumping Margin	US\$/MT	****
4	Dumping Margin %	Range	20%-30%

H. INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Views of other interested parties

None of the importers, consumers, exporters and other interested parties has filed any comment or submissions with regard to injury and causal link.

H.2. Views of Domestic Industry

1. The domestic industry has submitted as follows with regard to injury and causal link:
 - i. The imports are still continuing and are being reported at low and dumped prices.
 - ii. Imports from China have increased in the period of investigation as compared to base year, 2012-13 as well as immediately preceding year, 2014-15.
 - iii. Dumped imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry.
 - iv. The landed price of imports is not only below selling price of the domestic industry but also below cost of sales and non-injurious price of the domestic industry.
 - v. Both dumping margin and injury margin in the POI are positive and significant.
 - vi. Continued dumped imports from the subject country as well as other sources would suppress the prices of the domestic industry and prevent the price increases.
 - vii. Performance of the domestic industry has shown improvement in terms of production and capacity utilization. Further, the domestic industry has been able to make some profits.
 - viii. Growth of the domestic industry is positive in terms of some of the parameters such as production, capacity utilization, profits, cash profits and return on investments. However, sales and market share have not shown expected improvement despite increase in demand.

- ix. The circumstances, which were prevalent at the time of previous investigations, are very much in existence even till date. There has been no change in the circumstance, which could suggest that the dumping would not recur at the aggravated level at which it was at the time of original investigation.

H.3. Examination by the Authority

31. The injury analysis made by the Authority here under addresses the various submissions made by the interested parties.
32. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....” In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
33. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.
34. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry, Para (iv) of Annexure-II of the Anti-dumping Rules states as follows.
- “The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.”*
35. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.
36. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II(iv) of the Rules supra.
37. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country.

i. Assessment of Demand

38. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below:

Demand in the country

Particulars	UOM	2012-13	2013-14	2014-15	POI*
Demand - excluding captive					
Subject Country – China	MT	906	2,170	532	2,013
Countries attracting ADD	MT	3,997	3,046	4,069	2,270
Other Countries	MT	9,626	10,084	8,944	15,103
Sales of Domestic industry	MT	6,150	6,848	7,172	7,161
Other Indian Producers	MT	2,592	2,592	3,293	3,293
Total Demand	MT	23,271	24,740	24,010	29,840
Demand - including captive	UOM				
Subject Country – China	MT	906	2,170	532	2,013
Countries attracting ADD	MT	3,997	3,046	4,069	2,270
Other Countries	MT	9,626	10,084	8,944	15,103
Sales of Domestic industry	MT	6,195	6,905	7,238	7,235
Other Indian Producers	MT	5,400	5,400	6,720	6,720
Total	MT	26,124	27,605	27,503	33,340
Trend	Indexed	100	106	105	128

39. The Authority notes that the demand for the product under consideration has increased over the injury period, both including and excluding captive consumption by Asian Paints.

ii. Volume Effect of Dumped Imports and Impact on Domestic Industry

Import volume and market share

40. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports of the subject good from the subject country have been analyzed as under:

Particulars	UOM	2012-13	2013-14	2014-15	POI*
Imports Volume					
Subject Country – China	MT	906	2,170	532	2,013
Countries attracting ADD	MT	3,997	3,046	4,069	2,270
Other Countries	MT	9,626	10,084	8,944	15,103
Total Imports	MT	14,529	15,300	13,545	19,386

Consumption (incl. captive)	MT	26,124	27,605	27,503	33,340
Consumption (excl. captive)	MT	23,271	24,740	24,010	29,840
Production DI (incl. captive)	MT	7,196	6,889	6,880	7,358
Subject imports in relation to					
Total Imports	%	6%	14%	4%	10%
Consumption (incl. captive)	%	3%	8%	2%	6%
Consumption (excl. captive)	%	4%	9%	2%	7%
Production (incl. captive)	%	13%	32%	8%	27%
Production (excl. captive)	%	13%	32%	8%	28%

41. It is noted that imports of the product under consideration from subject country have increased over the injury period and are still significant and at dumped prices in absolute terms. Further, subject imports in relation to production and consumption have also increased over the injury period, despite existence of anti-dumping duty. The Authority also notes that the DI has operated at full capacity which shows that imports are inevitable in view of demand and supply gap. But such imports are at dumped process causing injury to the domestic industry.

iii. Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry

a. Price Undercutting

42. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex-factory level.
43. Price undercutting has been assessed by comparing the landed price of imports with the domestic selling price in India of the subject goods during the period of investigation. It would be seen that the landed price of imports without anti dumping duty is lower than the selling price of the domestic industry and would result in significant price undercutting should the present anti dumping duty be allowed to expire, as shown in the following table:

Particulars	UOM	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Net Selling Price	Rs./Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100.00</i>	<i>108</i>	<i>109</i>	<i>118</i>
Landed Price	Rs./Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100.00</i>	<i>103</i>	<i>113</i>	<i>112</i>
Price Undercutting without ADD	Rs./Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100.00</i>	<i>150</i>	<i>72</i>	<i>162</i>
Price Undercutting	%	***	***	***	***
<i>Range</i>		<i>5-15%</i>	<i>10-20%</i>	<i>5-15%</i>	<i>10-20%</i>

b. **Price Underselling**

44. The Authority notes that the price underselling is an important indicator of assessment of injury. Non injurious price has been worked out and compared with the landed value of the subject goods to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been determined considering the cost of production of the domestic industry for the product under consideration during the POI, in POI in accordance with Annexure III of the Anti-dumping Rules.

Particulars	\$USD /MT
Non injurious price	****
Landed value	****
Injury margin	****
Injury margin % Range	10-20

45. It is seen that the landed price of the subject goods from China was significantly lower than the NIP determined for the domestic industry.

c. **Price suppression/depression**

46. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown as per the table below:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI*
Cost of Sales	Rs./Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>110</i>	<i>113</i>	<i>100</i>
Selling Price	Rs./Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>108</i>	<i>109</i>	<i>118</i>
Landed Price	Rs./Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>103</i>	<i>113</i>	<i>112</i>

47. It is noted that whereas the cost of sales have declined over the injury period, the selling price of the domestic industry has increased. Thus, there is no price suppression and depression in the domestic market. However, the landed price of imports without anti-dumping duty is significantly below the selling price as well as the cost of sales of the domestic industry, which is likely to lead to price suppression/depression in case of cessation of anti-dumping duties.

iv. **ECONOMIC PARAMETERS OF THE DOMESTIC INDUSTRY**

48. Annexure II to the AD Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the AD Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

49. Accordingly, various economic parameters of the Domestic Industry are analyzed herein below.

a. **Production, Capacity, Capacity Utilization & Sale Volume**

50. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity & capacity utilization was as follows:

Particulars	UOM	2012-13	2013-14	2014-15	POI*
Capacity	MT	7,000	7,000	7,000	7,000
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Production	MT	6648	6,889	6,880	7,358
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>104</i>	<i>103</i>	<i>111</i>
Capacity Utilization	%	95%	98%	98%	105%
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>104</i>	<i>103</i>	<i>111</i>
Domestic sales	MT	6,150	6,848	7,172	7,161
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>111</i>	<i>117</i>	<i>116</i>

51. It is noted that capacity of the domestic industry has remained constant during the entire injury period. Performance of the domestic industry in terms of production and sales has improved as a result of anti-dumping duty on dumped imports in force.

b. **Market Share in Demand**

52. The effects of the dumped imports on the market share of the domestic industry have been examined as below:

Market Share (incl. captive)	UOM	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Subject Country - China	%	3%	8%	2%	6%
Countries attracting ADD	%	15%	11%	15%	7%
Other Countries	%	37%	37%	33%	45%
Domestic industry	%	24%	25%	26%	22%
Other Indian Producers	%	21%	20%	24%	20%
Total	%	100%	100%	100%	100%
Market Share (excl. captive)					
Subject Country - China	%	4%	9%	2%	7%
Countries attracting ADD	%	17%	12%	17%	8%
Other Countries	%	42%	41%	37%	50%
Domestic industry	%	26%	28%	30%	24%
Other Indian Producers	%	11%	10%	14%	11%
Total	%	100%	100%	100%	100%

53. It is noted that market share of the domestic industry has decreased in the POI as compared to the base year whereas market share of the subject country has increased over the injury period. Market share of other Indian producers has remained at the same level over the injury period. Further, market share of other countries attracting ADD has also decreased over the injury period; whereas market share of other countries (not attracting ADD) has increased. Considering the positive price undercutting and increase in market share of China, it is concluded that the market share of the domestic industry has declined as a direct result of dumped imports from China PR.

c. **Profit/Loss, Cash Flow, Return of Investment**

54. Performance of the domestic industry with regard to profits, return on investment and cash flow is as follows:

Particulars	UOM	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Cost of sales	Rs/KG	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>110</i>	<i>113</i>	<i>100</i>
Selling price	Rs/KG	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>108</i>	<i>109</i>	<i>118</i>
Profit/(Loss)	Rs/KG	(***)	(***)	(***)	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>-100</i>	<i>-128</i>	<i>-159</i>	<i>90</i>
Profit/(Loss)	Rs. Lacs	(***)	(***)	(***)	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>-100</i>	<i>-143</i>	<i>-186</i>	<i>105</i>
Cash Profit	Rs. Lacs	(***)	(***)	(***)	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>-100</i>	<i>-153</i>	<i>-204</i>	<i>147</i>
Profit before Interest and Tax	Rs. Lacs	(***)	(***)	(***)	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>-100</i>	<i>-141</i>	<i>-182</i>	<i>103</i>
Return on Capital Employed	%	(***)	(***)	(***)	***
<i>Range</i>		<i>-(10-20%)</i>	<i>-(20-30%)</i>	<i>-(30-40%)</i>	<i>10-20%</i>

55. It is noted that the domestic industry were incurring losses upto 2014-15 on account of presence of dumped imports in the domestic market. The domestic industry made some profits in the POI. Similarly, profit before interest, cash profit and return on investment have become positive in the POI after continuous losses up to 2014-15 but the return on capital employed is below the benchmark return of 22%.

d. **Inventories**

56. Inventories with the domestic industry is as follows:

Particulars	UOM	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Average stock	MT	226	478	257	53
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>203</i>	<i>109</i>	<i>22</i>

57. Inventories with the domestic industry increased significantly in 2013-14, declined in 2014-15 and then increased again in the POI.

e. **Productivity**

58. From the information given below, the Authority notes that Productivity in terms of productivity per day as well as per employee has increased in the POI, which is commensurate with the movement of production.

Particulars	UOM	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Productivity	Per Day	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>104</i>	<i>103</i>	<i>111</i>
Productivity	Per Emp	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>104</i>	<i>102</i>	<i>109</i>

f. **Employment and Wages**

59. It is noted from the table below that the level of employment has remained at similar level during the entire injury period. However, wages paid have increased up to 2013-14 and then declined in the POI:

Particulars	UOM	2012-13	2013-14	2014-15	POI
No of Employees	Nos	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>102</i>	<i>102</i>
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>101</i>	<i>98</i>	<i>94</i>
Wages	Rs/KG	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>106</i>	<i>103</i>	<i>86</i>

g. **Magnitude of Dumping**

60. The dumping margin determined in respect of the producers/exporters from the subject country is significant.

h. **Growth**

61. The Authority notes from the table below that the domestic industry has shown positive growth in terms of both, volume and price parameters in the Period of Investigation, as an effect of anti dumping duty being in place.

Growth	UOM	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Production	%	--	4%	0%	7%
Domestic Sales Volume	%	--	11%	5%	-
Capacity Utilization	%	--	3%	0%	7%
Selling price domestic	%	--	***	***%	***%
Profit Before Tax	%	--	(***)	(***)	***
Cash Profit	%	--	(***)	(***)	***
Return on capital employed (NFA basis)	%Range	--	-5 to -15%	-5 to -15%	35-45%

i. **Ability to raise capital investment**

62. The Authority notes that the performance of the domestic industry has improved. However, dumping has continued and would affect the domestic industry's ability to raise capital.

j. **Level of dumping & dumping margin**

63. It is noted that subject country imports are entering the country at dumped prices and that the margin of dumping is significant.

k. **Factors Affecting Domestic Prices**

64. The examination of the import prices from the subject country, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market, etc. shows that the landed value of imported material from the subject country is below the selling price and the non-injurious price of the domestic industry, causing significant price undercutting as well as price underselling in the Indian market. The benchmark for the Indian producers' prices is the import prices from various sources, including the subject countries. There is no viable substitute to this product. Thus, the principal factor affecting the domestic prices is the landed value of the imports of subject goods from subject country.

v. **Conclusion on injury**

65. After examining and analyzing the facts and figures concerning injury to the domestic industry, the Authority concludes that despite the presence of anti-dumping duties, imports from China are entering at dumped prices. Dumped imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry. The landed price of imports is not only below selling price of the domestic industry but also below cost of production and non-injurious price of the domestic industry. Both dumping margin and injury margin in the POI are positive and significant. Performance of the domestic industry has shown improvement in terms of production and sales volumes. Performance of the domestic industry has also shown improvement in terms of price parameters as the domestic industry has made some profits in the POI.

I. **Other Known Factors & Causal Link**

66. The Authority examined whether other known factors could have caused injury to the domestic industry as follows:

(1) **Volume and value of imports not sold at dumped prices:** - Imports of product under consideration from Chinese Taipei, Russia and European Union (excluding Sweden) are attracting anti dumping duties. Imports of product under consideration from all other countries are either low in volume or at high prices and are not causing injury to the domestic industry, except Saudi Arabia and Sweden. The Authority had earlier initiated investigations against Saudi Arabia and terminated the said investigations as the dumping margin was found to be below de-minimus. Anti dumping duty on imports from Sweden were revoked in 2011.

(2) **Contraction in demand:** The demand of the product under consideration has shown positive growth. Possible decline in demand could not have caused injury to the domestic industry.

(3) **Changes in the pattern of consumption:** - The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone material change against the product under consideration. Therefore, changes in the pattern of consumption cannot be considered to have caused injury to the Domestic Industry.

(4) **Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers:** - The Authority notes that there is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the domestic industry.

(5) **Developments in technology:** - The Authority also notes that technology for production of the product has not undergone any change.

(6) **Export performance:** The performance of the domestic industry and injury thereto has been examined with respect to the domestic performance to the extent possible. Possible deterioration in the

export performance of the domestic industry is, therefore, not a possible cause of injury to the domestic industry.

(7) **Performance of other products being produced and sold by the domestic industry:** The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the domestic industry has not affected the assessment made by the Authority of the domestic industry's performance. The information considered by the Authority is with respect to the product under consideration only.

(8) **Productivity of the domestic industry:** The Authority notes that the productivity of the domestic industry has followed the same trend as production and increased. Deterioration in productivity is not a cause of injury to the domestic industry.

67. The Authority concludes that while the known other factors listed above do not appear to have caused the injury determined. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows that the performance of the domestic industry has improved as a result of imposition of anti dumping duty. However, significant volumes of imports from the subject country at dumped prices continue to enter the country. The Authority is of the view that material injury would be caused to the domestic industry by dumped imports in case of cessation of anti dumping duty.

J. Conclusion on injury and Causation

68. The Authority notes that the volume of dumped imports from the subject country in absolute terms and relative to apparent consumption and production in India has been significant despite the fact that anti dumping duty is in force. It is noted that growth of the domestic industry in terms of all economic parameters like production, capacity utilization, domestic sales and market share, has been positive. The domestic industry has also started making profits in the POI. However, imports continue to enter at dumped prices and would cause significant price undercutting and underselling in the absence of anti dumping duty. It is noted that dumping of the subject goods has continued, however, there is no current injury to the domestic industry. Therefore, the Authority has conducted analysis of likelihood of continuation of dumping and its consequent effect on the performance of the domestic industry as detailed in the subsequent paragraphs.

K. Likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury

69. The Authority observed that this is a sunset review investigation and the focus of this investigation is to examine the likely scenario of continued dumping and consequent injury if the anti dumping duties were to be allowed to expire even if there is no current injury. It is noted that the subject imports are still entering into the domestic market at dumped and injurious price.

K.1 Submissions by the domestic industry

70. Following are the submissions made by the domestic industry with regard to likelihood of continuation of dumping and consequent recurrence of injury –

- i. Dumping Margins determined in previous investigation and present petition are positive and significant. This clearly shows likelihood of dumping and consequent injury in the event of cessation of anti-dumping duty. In the previous investigation the Authority attributed a dumping margin ranging from 50-60% for both cooperating and non-cooperating exporters. In the current investigation also, the dumping margin is significant.
- ii. Producers of subject goods in the subject country maintain huge capacities. The production of Pentaerythritol in China is nearly 3.4 lac MT per annum. The largest producer, Hubei Yihua Group LLC produces 1.2 lac MT. Hubei Yihua Group LLC occupies 70% of Chinese domestic sales.
- iii. The foreign producers are intensely focused on exports. Dumping to third countries is significant. In the event of cessation of anti dumping duty, these exporters are likely to increase their exports to India at dumped prices.

- iv. Petitioner has analyzed the exports from China to third countries as per China customs and has determined third country dumping margin and injury margin on country-wise basis. It would be seen that significant volume of exports from China to various destinations are at dumping and injurious prices.
- v. The Indian market is highly price sensitive. The consumers decide their procurement, with the price being the foremost consideration. Such being the case, availability of such low priced imports from the subject country in the market would definitely cause an adverse impact on the Domestic Industry. This is further established by the long term dumping practice by the subject country.
- vi. The prices at which subject goods are being imported are substantially lower than the price at which the goods are being sold in the domestic market. Therefore, in case of expiry of duty, exporters would further channelize their output in the Indian market as they are already holding excessive capacities and are in fact selling subject goods to third countries at substantially lower prices.

K.2 Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties

71. None of the producers/exporters/importers/other interested parties has made any submissions in this regard.

K.3 Examination by the Authority

72. The Authority has examined the contention of the domestic industry and other interested parties to examine likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. The following analysis shows that there is likelihood of continuation of dumping and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of *anti-dumping* duties:

i. Level of current and past dumping margin:

73. Considering the dumping margin determined by the Authority in the previous investigation and the dumping margin now assessed, it is quite evident that the exports were continued to be made at dumped prices and are likely to continue with cessation of anti dumping duties. Volume of dumped imports has increased even after imposition of anti-dumping duties. Further, the volume of imports is likely to increase further in the event of cessation of anti dumping duties, given the significant price undercutting and underselling during the injury period.

ii. Price attractiveness of Indian market

74. The price, at which the subject goods are being exported by China PR to India, is an indicator of the likelihood of continuation/intensification of dumping. At the current landed price in India, there is price undercutting during POI, both with and without anti dumping duty. Thus, with the cessation of anti-dumping duty, the Indian prices would be too attractive for the Chinese producers to intensify their exports to India at dumped prices and there is strong likelihood that Indian consumers would resort to large scale imports of the subject goods from China.

iii. Export orientation of Chinese producers

75. Information on exports from China to various countries provided by the petitioner has been analyzed. It is noted that significant volume of exports from China to various destinations are at dumping and injurious prices. In the event of cessation of duty, the exporters from subject country are likely to increase their exports to India at dumped prices.

iv. Vulnerability of Domestic Industry in terms of price sensitivity of the product and the Indian market

76. The Indian market is highly price sensitive. The consumers decide their procurement, with the price being the foremost consideration. Such being the case, availability of such low priced imports from the subject country in the market would cause an adverse impact on the Domestic Industry. This is further

established by the long term dumping practice by the subject country. Thus, dumping and consequent injury to the Domestic Industry is likely to recur in the event of cessation of anti dumping duty.

v. **Huge Production Capacity in China**

77. Considering the information available on record, it is noted that the producers of the subject goods in subject country hold significant production capacity which is far more than Indian demand. Thus, cessation of anti-dumping duty is likely to lead to surge in dumped imports from subject country.

vi. **Conclusion on Likelihood of dumping and injury**

78. Considering the current level of imports from the subject country, despite continued imposition of anti dumping duty, the Authority concludes that there exists likelihood of intensified dumping and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of anti dumping duty. It is further noted that the import prices would undercut the domestic prices and would also have a significant suppressing effect on the domestic prices.

L. Magnitude of Injury and injury margin

79. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority in terms of Annexure III to the AD Rules has been compared with the landed value of the exports from the subject country for determination of injury margin during the POI and the injury margin so worked out is as under:

Particulars	Unit	POI
Non injurious Price	\$USD/MT	***
Landed Value	\$USD/MT	***
Injury margin	\$USD/MT	***
Injury margin	%	***
Injury margin	Range	10-20

M. Post Disclosure Comments

80. Following comments have been made by the Domestic Industry in response to the Disclosure Statement:

M.1. Submissions by the Domestic Industry

81. The domestic industry inter alia submitted as follows

- Authority may provide the documents such as break up of non injurious price, verification reports of exporters (non confidential version) and communications sent by the Authority to all the interested parties and their replies.
- Anti dumping duty may be imposed as a fixed quantum (fixed form of duty) on the subject goods. Reason being, the product under consideration is attracting fixed quantum of ADD and therefore the same may be continued.
- The duty should be levied in US\$

M.2. Submissions of other interested parties

82. None of the producers/exporters/importers/other interested parties has made any submissions in this regard.

M.3. Examination by the Authority

83. The Authority notes that post-disclosure comments/submission made by the domestic industry are mostly reiterations of earlier submissions, which have already been examined suitably and adequately and properly addressed in the disclosure statement or relevant paras of the present finding. The authority further considers as follows with regard to fresh issues raised by the domestic industry.

- i. As regards the submissions of the domestic industry concerning determination of non-injurious price (NIP), the Authority notes that the detailed guidelines for computation of NIP is laid down under Annexure III of the Anti-dumping Rules and the same has been adopted while determining NIP in the present investigation.
- ii. As regards the submission of the domestic industry concerning form of duty, the Authority notes that as per the Anti-dumping Rules, the mandate of the Designated Authority is to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the adequate quantum of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, suitability of the form of the anti-dumping measures is decided by taking in to consideration the facts of a case.

N. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES:

84. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country/territory in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

85. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

O. CONCLUSIONS

86. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in this finding and on the basis of the above analysis of the state of continuation of dumping and consequent injury and likelihood of continuation/recurrence/ intensification of dumping and injury, the Authority concludes that:

- i. There is continued dumping of the product concerned from China PR, causing injury to the domestic industry.
- ii. Imports are significantly undercutting and underselling the prices of the domestic industry.
- iii. Cessation of *anti-dumping* duty is likely to lead to continuation and recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

P. RECOMMENDATIONS

87. Accordingly, the Authority recommends that the revised and continuation of anti dumping duties be imposed from the date of issue of notification by the Central Government on all imports of Pentaerythritol

falling under chapter 29 of Custom Tariff Classification Act 1975, originating in or exported from China PR. The anti dumping duty shall be the amount mentioned in Column No. 9 of the following table.

Sl. No	Sub-heading	Description of goods	Specification	Country of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	2905	Pentaerythritol	Any	China	China	Any	Any	185.15	MT	US\$
2	2905	Pentaerythritol	Any	China	Any	Any	Any	185.15	MT	US\$
3	2905	Pentaerythritol	Any	Any	China	Any	Any	185.15	MT	US\$

Q. Further Procedures

88. An appeal against this notification, after its acceptance by the Central Government, shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

Dr.INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority